RNI NO. CHAHIN00468

अंक 4 । आश्विन-कार्तिक विक्रमी 2078 । अक्तूबर 2021

सदन संदेश

हरियाणा विधान सभा की मासिक पत्रिका

हर झंझावात में चट्टान की तरह अडिग है भारत का यह लोकतंत्र

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारत के संविधान में लगाया गया देश की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने वाला चित्र।

खेल-खेल में सोना गढ़ रही हरियाणा की मिट्टी

हरियाणा की खेल प्रतिभाओं ने विश्व पटल पर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। टोक्यो में आयोजित 29वें ओलंपिक खेलों की बात हो या 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इसी शहर में खेले गए पैरा ओलंपिक मुकाबलों की बात हो दोनों ही खेल महाकुंभों में इन खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है। ओलंपिक में भारत के 119 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 32 होनहार हरियाणा के रहे। इन खिलाड़ियों में श्री नीरज चौपड़ा ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। कुश्ती में रवि कुमार ने रजत पदक और बजरंग ने कास्य पदक से देश का मान बढ़ाया। इसी प्रकार हॉकी में सुरेंद्र कुमार और सुमित ने कास्य पदक जीतकर विश्व में हरियाणवी मिट्टी का लोहा मनवाया। प्रदेश के लिए गौरव के प्रतीक बने इन खिलाड़ियों के लिए हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र में पहले दिन मानपत्र पढ़ा गया।

खेल के क्षेत्र में इन उपलब्धियों के लिए जहां इन खिलाड़ियों की अथक मेहनत प्रमुख कारण है, वही प्रदेश सरकार की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली खेल नीतियां भी बड़ा संबल बनी हैं। खेल जगत के विशेषज्ञों ने खुले मन से स्वीकार किया है कि खेलों के विकास के लिए हरियाणा सरकार की नीतियों ने नया रास्ता दिखाया है। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए जो भी काम किए गए हैं, उसी का परिणाम रहा कि भारत को टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने की हिम्मत दी।

ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार विशेष पुरस्कारों से सम्मानित करती है। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ और कॉस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम दी जाती हैं। इसके अलावा ऐसे खिलाड़ियों के कोच को भी 20 लाख रुपये की राशि इनाम के रूप में दी जाती है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में चौथे स्थान पर आने वाली महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को भी इनाम दिया गया। इस टीम के 9 सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा हुई थी। कुल मिलाकर सरकार की ओर से ओलंपिक खिलाड़ियों को 25 करोड़ 40 रुपये के नकद पुरस्कार से नवाजा है।

इसी प्रकार पैराओलंपिक में भारत के कुल 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें 19 हरियाणा के रहे। इन 19 में से 5 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते हैं। सरकार ने सभी 19 खिलाड़ियों को 26.85 करोड़ रुपये के पुरस्कार बांटे। सरकार की ओर से बड़े स्तर पर मिल रहा प्रोत्साहन खिलाड़ियों की सफलता का बड़ा कारण है। पैराओलंपिक की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने जैसा कि कहा भी है कि जिस तरह से देशवासियों और प्रदेश व केंद्र सरकार से सम्मान मिला है, वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

विधान पालिका का रुख खेल और खिलाड़ियों के प्रति सदैव सकारात्मक रुख रहा है। इसी वर्ष 6 अगस्त को लोक सभा में पेश की गई एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में खेल तंत्र को मजबूत करने के प्रभावी सुझाव दिए हैं। इसमें कहा गया है कि एथलीटों को निजी स्रोतों से भी फंड जुटाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मेरी सभी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों तथा खेल प्रशासन से जुड़े लोगों से अपील है कि वे खेल को अपने निजी कैरियर के तौर पर ही नहीं अपितु देश के सम्मान के साथ जोड़ कर देखें, तभी हमारे नवोदित खिलाड़ी उनके प्रेरणा पाकर उपलब्धियों की नई गाथा लिख सकेंगे।

ज्ञान चंद गुप्ता
माननीय अध्यक्ष
हरियाणा विधान सभा

सदन संदेश

हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका
अंक 4, आश्विन-कार्तिक 2078, अक्तूबर 2021
www.haryanaassembly.gov.in

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी
(माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा)

प्रकाशक
श्री राजेन्द्र कुमार नांदल जी
सचिव, हरियाणा विधानसभा सचिवालय

प्रधान संपादक
दिनेश कुमार
मीडिया एवं संचार अधिकारी, हरियाणा विधानसभा

सहयोगी
तेजपाल राठी
जन-संपर्क अधिकारी, हरियाणा विधानसभा
अंकित वत्स
अनुसंधान अधिकारी, हरियाणा विधानसभा
नवीन भारद्वाज
अनुसंधान अधिकारी, हरियाणा विधानसभा

संपर्क
सदन संदेश
हरियाणा विधानसभा सचिवालय
सेक्टर 1, चंडीगढ़-160001
☎ 0172-2741525-28
✉ itcellvs@hry.nic.in

अक्तूबर — आश्विन–कार्तिक

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
31 कृ.दशमी					1 कृ.दशमी	2 कृ.एकादशी
3 कृ.द्वादशी	4 कृ.त्रयोदशी	5 कृ.चतुर्दशी	6 आश्विन अमावस्या	7 शु.प्रतिपदा	8 शु.द्वितीया	9 शु.तृतीया /चतुर्थी
10 शु.पंचमी	11 शु.षष्ठी	12 शु.सप्तमी	13 शु.अष्टमी	14 शु.नवमी	15 शु.दशमी	16 शु.एकादशी
17 शु.द्वादशी	18 शु.त्रयोदशी	19 शु.चतुर्दशी	20 आश्विन पूर्णिमा	21 कार्तिक कृ.प्रतिपदा	22 कृ.द्वितीया	23 कृ.तृतीया
24 कृ.चतुर्थी	25 कृ.पंचमी	26 कृ.पंचमी	27 कृ.षष्ठी	28 कृ.सप्तमी	29 कृ.अष्टमी	30 कृ.नवमी

2	शनिवार	महात्मा गाँधी जयन्ती
7	वीरवार	महाराजा अग्रसेन जयन्ती
15	शुक्रवार	दशहरा
19	मंगलवार	मिलाद-उन-नबी /ईद-ए-मिलाद
20	बुधवार	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती
24	रविवार	करवाचौथ

इस अंक में

नई परंपरा : शून्यकाल से शिखर की ओर (लेख पृष्ठ 7 पर)

प्राक्कथन ◆	खेल में सोना गढ़ रही हरियाणा की धरती	3
संपादकीय ◆	लोकतंत्र को भीड़ के हवाले न होने दें	5
मानसून सत्र ◆	सार्थक बहस, उत्कृष्ट कार्य	6
ध्यानाकर्षण ◆	विधायकों ने उठाए जनहित के मामले	11
कार्यवाही ◆	सदन ने किए 11 विधेयक पास	12
प्रश्नकाल ◆	निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की मुहिम	13
मुलाकात ◆	श्री अमित शाह ने मानीं हरियाणा की मांगें	16
विचार विमर्श ◆	लोक सभा अध्यक्ष से विधायी कामकाज पर चर्चा	17
साक्षात्कार ◆	श्री दुष्यंत चौटाला सबसे युवा उपमुख्यमंत्री	18
निर्णय ◆	श्री प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल	20
अधिनियम ◆	दशकों बाद बनी प्रवर समिति	21
कोरोना संकट ◆	देश का विधायी तंत्र रहा सक्रिय	22
ऑनलाइन सम्मेलन ◆	हरियाणा ने अभिनव प्रयोगों से लूटी वाहवाही	23
वर्चुअल संवाद ◆	राजनीति से ऊपर उठ ली कोरोना से जंग	24
अधिक वसूली ◆	जनसेवक की भूमिका में नजर आए अध्यक्ष	27
बैठक ◆	दुल्हन की तरह सजेगी हरियाणा विधान सभा	28
जन्मदिन ◆	समाज सेवा को समर्पित दिनचर्या	29
मार्गदर्शन ◆	सरकारी खर्च पर रहेगी विधायिका की नजर	30
विधान विमर्श ◆	महाभारत से हुआ विचार परंपरा में परिवर्तन	32
संविधान संकल्पना ◆	भारत के गौरवशाली अतीत की झलक	33
तीज उत्सव ◆	पहली बार मनाया सावन का त्योहार	35
समीक्षा ◆	सदन संदेश में हरियाणा के उत्थान की झलक	38

महापुरुषों की कड़ी मेहनत से मिला है लोकतंत्र

इसे भीड़ के हवाले न होने दें

दिनेश कुमार
मीडिया एवं संचार अधिकारी
हरियाणा विधान सभा

अक्तूबर माह लोकतंत्र के पुरोधा महापुरुषों के स्मरण का महीना है। ये ऐसे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ देश-समाज के लिए अर्पित किया। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, देश को एकता के सूत्र में संवारने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल, किसानों और जवानों के लिए जीवन समर्पित करने वाले लाल बहादुर शास्त्री, आदि कवि महर्षि बाल्मीकि, समाजवाद के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन, दूसरी आजादी के नायक माने जाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण, साहित्य से दुनिया में सकारात्मक विचार को प्रवाहमान करने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार और नारी गरिमा की प्रतीक रानी दुर्गावती की जयंती राष्ट्र इसी माह मना रहा है।

ये सब ऐसे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की चिंता न करते हुए समाज के लिए जीने का संकल्प लिया। लोकतंत्र रक्षक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती और पुण्यतिथि के दोनों ही महत्वपूर्ण दिन अक्तूबर माह में आते हैं। लोकनायक को आंदोलन के पुरोधा के रूप में जाना जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका और जेल यातना से लेकर 1975 के आपातकाल तक उनके आंदोलनों का सिलसिला जारी रहा। आपातकाल के विरोध में उनकी अगुवाई में जहां पूरा देश लामबंद हो गया, वहीं इस आंदोलन से बड़ी संख्या में नेतृत्व क्षमता का भी सृजन हुआ।

हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, वह इन महापुरुषों की ही देन है। लोकतंत्र रूपी वटवृक्ष को पल्लवित-पुष्पित करने के लिए इन्होंने अपने जीवन का श्रेष्ठतम अर्पित किया। आज कुछ लोग आंदोलनों के नाम पर इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को नकारने की चेष्टा कर रहे हैं। लोकतंत्रीय प्रणाली से चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर हमले कर पूरी व्यवस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है। आखिर देश के लोगों ने जिन पर विश्वास जताकर कानून बनाने का अधिकार दिया, उनके बनाए हुए कानूनों को वे लोग नकार रहे हैं, जो चुनावी दौड़ में जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर सके। अब वे जनता को उनके प्रतिनिधियों का रास्ता रोकने के लिए उकसा रहे हैं, क्या वे लोकतंत्र की राह में रोड़ा नहीं अटका रहे?

जिन महापुरुषों ने हमें लोकतंत्रीय व्यवस्था दी, उन्होंने हमें आंदोलन की राह भी दिखाई है। दरअसल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलनों के माध्यम से वैश्विक महाशक्ति बने अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने जिस संविधान को राष्ट्र के लिए अंगीकृत किया वह संविधान असहमति वाले विचार का भी समादर करना सिखाता है। इसके विपरीत आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के नाम पर लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के हाथों में सौंपने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता लोकतंत्र पर हावी होते भीड़ तंत्र की भूमिका पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा है 'चुनाव हारने के पश्चात भीड़ तंत्र के सहारे सत्ता हथियाने की कोशिश निंदनीय एवं चिंताजनक है। यह लोकतंत्र पर आघात है। लोकतांत्रिक राजनीति में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को उनके विधान सभा क्षेत्र में जाने से रोकना उनके साथ दुर्व्यवहार करना लोकतंत्र की हत्या करने के समान है।' दरअसल आज वह समय आ गया है कि जब पूरा देश एकजुट होकर लोकतंत्र के प्रति आस्था प्रकट हुए भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करें, तभी इन महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाना सार्थक होगा।

बढ़ने लगी सत्रों की अवधि

मानसून सत्र : सार्थक बहस, उत्कृष्ट कार्य

मानसून सत्र से पहले 20 अगस्त को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र समयावधि और कार्य-उत्पादकता दोनों ही दृष्टि से उत्कृष्ट रहा है। सत्र की समाप्ति के अगले दिन 25 अगस्त को विधान सभा सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने इस संबंध में आंकड़े मीडिया के साथ साझा किए। उन्होंने गत 16 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन पत्रकारों के सम्मुख रखा। इस दौरान पत्रकारों ने शून्यकाल जैसी नई परंपरा शुरू करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष की प्रशंसा भी की।

विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने विधान सभा सचिवालय के आंकड़ों के हवाले से बताया कि कांग्रेस के पहले कार्यकाल में 2005 से 2009 तक 12 सत्र हुए थे, जिनमें मात्र 70 बैठकें हुई थीं। कांग्रेस के अगले कार्यकाल में सत्र और सिटिंग दोनों घटाए गए और वर्ष 2009 से 2014 तक 11 विधान सभा सत्रों में मात्र 56 बैठकें हुई थीं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से विधान सभा के सत्र और बैठकें दोनों बढ़ने शुरू हुईं। 2014 से 2019 तक 13वीं विधान सभा में 15 सत्रों का आयोजन हुआ था, जिनमें 84 सीटिंग रही थीं।

अच्छा होता कि कांग्रेस के नेता अपने कार्यकाल में स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत करते। आंकड़े गवाह हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में विधान सभा के न तो इतने लंबे सत्र चले और जो औपचारिकता भर चलते थे, उनमें विपक्षी विधायकों को बोलने का इस प्रकार अवसर नहीं दिया जाता था, जैसे अब मिल रहा है।

श्री कंवर पाल
संसदीय कार्यमंत्री

नवंबर 2019 में गठित 14वीं विधान सभा के अब तक के 6 सत्रों में कुल 31 बैठकें हुई हैं। 20 अगस्त से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान तीन बैठकों में 15 घंटे 34 मिनट कार्यवाही चली।

हरियाणा विधान सभा के इतिहास में पहली बार शून्यकाल कार्यसूची का हिस्सा बना है। मानसून सत्र की तीनों बैठकों में शून्यकाल के दौरान 42 विधायकों ने अपनी बात रखी, जिनमें से सबसे ज्यादा अवसर कांग्रेस के विधायकों को दिया गया। शून्यकाल में कांग्रेस के 18, भाजपा के 12, जजपा के 6 और छह निर्दलीय विधायकों को मौका दिया गया। इतना ही नहीं शून्यकाल और विधेयकों पर चर्चा के लिए विपक्षी विधायकों को दोगुना से भी ज्यादा समय दिया गया। इस दौरान सत्ता पक्ष को 107 मिनट, विपक्ष को 217 मिनट और निर्दलीय विधायकों को 22 मिनट का समय दिया। सदन में पारित 11 विधेयकों पर आयोजित विस्तृत चर्चा में 42 विधायकों ने भाग लिया।

मानसून सत्र के लिए विधान सभा सचिवालय को 247 तारांकित और 120 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनमें से 60 तारांकित और 56 अतारांकित प्रश्न कार्यवाही का हिस्सा बने। इसी प्रकार 5 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। विधान सभा सचिवालय को 5 स्थगन प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि 3 विधायी कारणों से अस्वीकृत करने पड़े। ■

शून्यकाल से शिखर की ओर

◆ दिनेश कुमार

हरियाणा विधान सभा में नई परंपराओं और नए आयोजनों की शुरुआत का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। इस क्रम में यहां गत 20 से 24 अगस्त तक आयोजित मानसून सत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। इस सत्र को हरियाणा विधान सभा के इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दौरान संसदीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक 'शून्यकाल' सदन की कार्यसूची का हिस्सा बना। विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा शुरू किए गए इस अभिनव प्रयोग से जहां विधायकों को तत्काल महत्व के मसले सरकार के संज्ञान में लाने का अवसर मिला वहीं, संवैधानिक नियम-परंपराओं के जानकार इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बेहतर प्रयास बता रहे हैं।

भारत में सभा-संवाद का इतिहास आदिकाल से माना जाता है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों की शासन पद्धति में सभाओं की सर्वोच्चता सदैव रही है। स्वाधीनता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने संसदीय नियमावली तैयार की, जिससे सदनों की गरिमा को और बढ़ाते हुए इन्हे शीर्ष स्थान पर रखा। कालांतर में देश की आवश्यकताओं के अनुसार ये नियम परिपुष्ट होते गए और इनमें नई परंपराएं भी स्थापित हुई। 60 के दशक में भारतीय संसद में 'शून्यकाल' की शुरुआत हुई।

'शून्यकाल' में सदन के सदस्य तत्काल महत्व के ऐसे मसले उठाते हैं, जिन्हें सरकार के ध्यान में अविलंब लाना आवश्यक समझा जाता है। धीरे-धीरे देश के अनेक राज्यों के विधान मंडलों में भी 'शून्यकाल' का आगाज हुआ। ये ऐसे मसले होते हैं, जिन पर देरी की गुंजाइश नहीं होती। जब ऐसे मामले उठते हैं और सदस्यों के मन को उद्वेलित करते हैं तो वे महसूस करते हैं कि वे सामान्य प्रक्रिया नियमों का अनुपालन करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि ऐसे मसले पर बात सदन द्वारा नियमित कार्यवाही शुरू करने से पहले ही होनी चाहिए।

हरियाणा विकासशील राज्यों में अग्रणी है। यहां नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। कृषि प्रधानता वाले इस राज्य में गत कुछ वर्षो से उद्योग-धंधों ने रफ्तार पकड़ी है। यहां का युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। खेल, कला, संगीत की बात हो या कारोबारी गतिविधियों की हर तरफ हरियाणवी प्रतिभाओं का डंका बज रहा है। इसके साथ ही यहां प्रायः नए मसले भी उठते रहे हैं। इनमें से अनेक का तात्कालिक महत्व रहता है। ऐसे में यहां 'शून्यकाल' की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग की अध्यक्षा प्रो. नवजोत के अनुसार तत्काल महत्व के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए 'शून्यकाल' बड़ा उपकरण है। वे कहती हैं कि हरियाणा विधान सभा में 'शून्यकाल' का शुरू होना पूरे उत्तर भारत की संसदीय परंपरा के लिए मील का पत्थर है। जनहित के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रयासपूर्वक 'शून्यकाल' का लाभ उठाना चाहिए।

हरियाणा विधान सभा में 20 अगस्त 2021

हरियाणा विधान सभा में अगस्त 2021 के मानसून सत्र की कार्यवाही का दृश्य।

को पहली बार 'शून्यकाल' कार्यसूची (List of Business) का हिस्सा बना। इस दिन की सुबह 11 बजे आयोजित कार्य मंत्रणा समिति (BAC) की बैठक में विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रस्ताव रखा कि माननीय विधायकों को तत्काल महत्व के विषयों पर अपनी बात रखने के लिए कुछ समय निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। बैठक में मौजूद सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तत्पश्चात उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल, विधान सभा उपाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह गंगवा और विधान सभा सचिव श्री राजेंद्र सिंह नांदल ने भी इस विचार की सराहना करते हुए सदन में 'शून्यकाल' शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी।

इसी दिन अर्थात 20 अगस्त 2021 को दोपहर 2 बजे शुरू हुए मानसून सत्र में प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात 3:11 बजे 'शून्यकाल' कार्यवाही का हिस्सा बना। यह सत्र 24 अगस्त तक चला और तीनों दिनों की बैठकों में प्रतिदिन प्रश्नकाल के बाद 'शून्यकाल' के लिए एक घंटा रखा गया। विधान सभा अध्यक्ष ने अधिक से अधिक विधायकों को बात रखने के अवसर प्रदान करने के लिए तय किया कि हर विधायक 3 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करे। उनका आग्रह इस बात पर ज्यादा रहा कि जो विधायक पहली बार चुनकर सदन में पहुंचे हैं, उन्हें अपने विचार रखने के लिए प्राथमिकता मिले। हालांकि कुछ पुराने सदस्य इस प्रयास में रहे कि उन्हें वरिष्ठता के आधार पर विशेष तवज्जो दी जाए, लेकिन विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता अपने निर्णय पर अडिग रहे और हर सदस्य को समान अवसर देते हुए सभी के लिए 3 मिनट का समय निर्धारित किया।

इस नियम का परिणाम यह रहा कि तीन दिनों की कार्यवाही में 42 विधायकों को बोलने का अवसर मिला, जिनमें सबसे ज्यादा विधायक इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहे। कांग्रेस के कुल 18 विधायकों को 'शून्यकाल' में बात रखने का मौका मिला। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के 12, जननायक जनता पार्टी के 6 और निर्दलीय विधायकों में से 6 विधायकों ने 'शून्यकाल' का लाभ उठाते हुए सदन पटल पर अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि विस अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 'शून्यकाल' के दौरान उठाए जाने वाले मसलों पर संबंधित मंत्री की ओर तुरंत जवाब की अपेक्षा नहीं है, फिर भी अगर मंत्री चाहे तो उठाए गए मसलों पर तथ्य रख सकते हैं। सदन की इस व्यवस्था से यह चर्चा काफी गंभीर

पीठासीन अधिकारी अधिकारी सम्मेलन का निर्णय लागू करने में हरियाणा अग्रणी

देहरादून में 18–19 दिसंबर 2019 को आयोजित पीठासीन अधिकारियों के 79वें अखिल भारतीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि देश के सभी विधान निकायों के सत्रों में शीघ्रता से शून्यकाल की शुरुआत की जाए। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में 'शून्यकाल सहित आंतरिक उपकरणों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र और क्षमता निर्माण को मजबूत करना विषय पर चर्चा करते हुए महसूस किया कि शून्यकाल, जहां कहीं भी व्यवहार में है, सदस्यों की क्षमता निर्माण और मामलों को सामने लाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। इसलिए, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत में सभी विधान निकाय अपने दैनिक सत्रों में शीघ्रता से शून्यकाल शुरू करने का प्रयास करें। यह सम्मेलन हरियाणा की 14वीं विधानसभा के गठन के करीब डेढ़ माह बाद आयोजित किया गया था। श्री ज्ञान चंद गुप्ता के विधान सभा अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला बड़ा औपचारिक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को वे पूरी शिद्दत से लागू कर रहे हैं। मानसून सत्र से शुरु हुआ शून्यकाल भी इसी कड़ी की महत्वपूर्ण श्रृंखला है।

ऐसे हुआ क्रमिक विकास

'शून्य काल' के संचालन से संबंधित मामले ने देश में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है। 4 से 6 फरवरी, 2003 तक मुंबई में हुए विधानमण्डलों के पीठासीन अधिकारियों के 66वें सम्मेलन में लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष तथा सम्मेलन के सभापति श्री मनोहर जोशी ने 'शून्य काल के विनियमन' के संबंध में पीठासीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया। समिति ने 29 मार्च 2003 को भोपाल में, 24 जून 2003 को जयपुर में, दिनांक 23 सितम्बर 2003 को नई दिल्ली में तथा दिनांक 14 नवम्बर 2003 को जम्मू में 4 बैठकें कीं। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- शून्य काल को 'विशेष उल्लेख' का नाम दिया जाए।
- विशेष उल्लेख मद प्रश्न काल के पश्चात लिया जाए।
- 'कोई सदस्य' विशेष उल्लेख के दौरान किसी मामले को उठाने की सूचना तभी दे सकेगा जब सही समय पर मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी।
- केवल उन्हीं मामलों को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए जो पिछले दिन की बैठक की समाप्ति के बाद और इस दिन की बैठक की शुरुआत से पहले उत्पन्न हुए हों।
- विशेष उल्लेख के दौरान उठाए जाने के लिए मामले को गंभीरता, महत्व तथा तात्कालिक आवश्यकता प्रमुख मानदण्ड होने चाहिए।
- बैठक से कम से कम एक घंटा पहले सूचनाएं दी जानी चाहिए।
- सूचना के मूल पाठ की शब्द सीमा अधिकतम 150 तक हो।
- विशेष उल्लेख की अवधि 20 मिनट होनी चाहिए। तथापि, यह अवधि विधानमंडल के सदस्यों की संख्या तथा अध्यक्षपीठ के विवेक पर निर्भर होने के कारण भिन्न–भिन्न हो सकती है; और
- यदि संबंधित मंत्री के पास सूचना तत्काल उपलब्ध है तो वह उठाये गये मामले का तुरंत उत्तर दे, अन्यथा मंत्री द्वारा मामले का शीघ्रातिशीघ्र उत्तर दिया जाए।

और सार्थक हो गई। अनेक जनहित के विषय सदन पटल पर आए तो सत्ता पक्ष की ओर से प्रभावी जवाब भी दिए गए। बड़ी तादाद में वे मसले चर्चा में आए जिन पर तुरंत कार्यवाही आवश्यक थी।

लोक सभा के दो प्रतिष्ठित पूर्व महासचिव श्री महेश्वर नाथ कौल और श्री श्याम लाल शकधर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' में लिखा है कि 'शून्य काल' को 'प्रश्न काल' की समाप्ति और दिन की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध मदों को लेने के बीच मध्यान्तर काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संसद की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होती है और 'प्रश्न काल' के बाद मध्याहन 12 बजे 'शून्य काल' शुरू होता है। यह आवश्यक नहीं कि 'शून्य काल' जैसा कि इस शब्द के अर्थ से प्रतीत होता है एक घंटे तक चलें। ■

रोचक है नाम की कहानी

'शून्यकाल' की शुरुआत भारतीय संसद से ही हुई है। यह विचार तब निकला जब सांसदों को राष्ट्रीय और अपने संसदीय क्षेत्र के अहम मुद्दों को उठाने की जरूरत महसूस हुई। यह भी कहा जाता है कि यह नाम अखबारों का दिया हुआ है। शुरुआत के दिनों में संसद में एक बजे भोजन अवकाश हुआ करता था। इससे पूर्व 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल के लिए समय निर्धारित रहता है। सदस्यों को प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद भोजन अवकाश तक बिना किसी पूर्व नोटिस के राष्ट्रीय मुद्दे उठाने का अच्छा मौका मिल जाता था। धीरे-धीरे यह समय 'शून्यकाल' के तौर पर जाना जाने लगा। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी 'शून्यकाल' की कार्यवाही को भी प्रसारित करने का निर्देश देने लगे, ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके।

संसद में समय के साथ बढ़ती गई शून्यकाल की लोकप्रियता

लोक सभा में 'शून्य काल' शब्द का उद्भव सन् 1960 के आस-पास हुआ जब प्रश्न काल के तुरन्त बाद सदस्यों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को स्थगन प्रस्ताव, व्यवस्था का प्रश्न इत्यादि के रूप में उठाया जाने लगा। यद्यपि अध्यक्ष इस प्रकार की अधिकांश सूचनाओं की अनुमति नहीं देते थे, किन्तु कभी-कभी सदस्यों को सभा के अन्दर उन मामलों का उल्लेख करने का अवसर मिल जाता था। इससे कुछ हद तक उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता था और इससे उनको थोड़ा संतोष हो जाता था कि कम से कम वे उन मामलों की ओर सभा और सरकार का ध्यान आकर्षित करने और उपयुक्त कार्यवाही की मांग करने में सफल रहे हैं।

धीरे-धीरे, प्रश्न काल के बाद और सभा में कार्य को सूचीबद्ध मदों को लेने से पहले के बीच के मध्यान्तर काल जिसे 'शून्य काल' के नाम से जाना जाता है का उपयोग सदस्य इस प्रकार के मामलों को उठाने में करने लगे और यह परिपाटी सभा की कार्यवाही का नियमित लेकिन अनभिज्ञान हिस्सा बन गई। इस समय का उपयोग वरिष्ठ सांसदों ने वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सभा तथा उसके माध्यम से राष्ट्र का ध्यान बड़ी दक्षता से आकर्षित किया। समय बीतने के साथ ही, शून्य काल की कार्यवाहियां मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आनी शुरू हो गईं, जिससे अधिकाधिक सदस्य इस तात्कालिक सहज सुलभ साधन का सहारा लेने को प्रोत्साहित हुए। कुछ वर्षों में यह परिपाटी बहुत से राज्य विधानमंडलों में भी लोकप्रिय हो गई। हालांकि 'शून्य काल' सदस्यों में लोकप्रिय और स्वीकार्य हो रहा था, किन्तु कई बार सदन के बहुमूल्य समय पर अप्रत्याशित अतिक्रमण कभी-कभी कुछ सदस्यों के उग्र और अनुशासनहीन और अभद्र आचरण को देखते हुए पीठासीन अधिकारियों द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती थी। इसके साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि 'शून्य काल' जीवन्त और महत्वपूर्ण बन चुका है। यह महत्वपूर्ण मामलों को उठाने और लोक शिकायतों को अभिव्यक्त करने का साधन था और इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि एक ओर यह मत था कि यह सामान्य कार्य के निपटान को सुनिश्चत करने में पीठासीन अधिकारियों के समक्ष बहुत बाधा है, किन्तु दूसरी ओर संसदीय परिपाटी में इसके योगदान के कारण इसे मौलिक चीज माना जाने लगा।

चूंकि इस प्रकार के मामलों को उठाने में लोक सभा का काफी समय लगता है इसलिए सन् 1990 में 'शून्य काल' को विनियमित करने का निर्णय लिया गया ताकि कार्य का सुचारू ढंग से निपटान सुनिश्चित किया जा सके और पीठासीन अधिकारी को पहले से यह भी पता चल सके कि सदस्य कौन से मुद्दे उठाना चाहते हैं।

तभी से 'शून्य काल' के दौरान कार्यवाही संचालन का प्रयास एक सतत् प्रक्रिया है। लोक सभा में एक के बाद एक आने वाले अध्यक्षों ने दलों के नेताओं के साथ की गई बैठकों तथा कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले पर विचार-विमर्श किया है। उन्होंने कई अवसरों पर नेताओं को यह सलाह दी है कि वे अपने दल के सदस्यों को आत्म-संयम बरतने के लिए समझाएं तथा यह बात भी समझाएं कि वे ऐसे मामलों, जो तात्कालिक राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं, को न उठाएं। ■

विधायकों ने माना बेहतर अवसर, सदन तक पहुंची जनता की आवाज

श्री इंदुराज नरवाल, बरौदा

हरियाणा विधान सभा में मानसून सत्र से 'शून्यकाल' का शुरू होना अच्छी शुरुआत है, उनके लिए यह खुशी की बात है। इसमें एक सुझाव यह है कि विधायकों को मौके पर ही जवाब मिलना चाहिए। सभी विधायकों को समान अवसर मिलना सराहनीय कार्य है।

श्री दीपक मंगला, पलवल

'शून्यकाल' की शुरुआत काफी अच्छी लगी। नए विधायकों को अपनी बात रखने का विशेष अवसर मिला है। इससे जहां विधान सभा में संसदीय परंपराएं पुष्ट हो रही हैं, वहीं विधायकों के विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को होगा।

श्री ईश्वर सिंह, गुहला

'शून्यकाल' में ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं, न कि मांगें। कई बार देखने में आया कि इस दौरान मांगें शुरू कर दी गईं। 'शून्यकाल' ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का होना चाहिए। लंबा खींचने से इसका भाव खत्म हो जाता है। इसमें सार्वजनिक हित निहित हों और तत्काल महत्व का विषय हो।

मोहम्मद इलियास, पुन्हाना

हरियाणा के इतिहास में पहली बार 'शून्यकाल' शुरू हुआ है। यह अच्छी परंपरा है। सभी वरिष्ठ और नए विधायकों को बराबर का मौका मिलता है। सभी विधायक जनता द्वारा समान पद्धति से चुनकर आते हैं। इसलिए उनके साथ वरिष्ठता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री देवेंद्र सिंह बबली, टोहाना

सत्र की अवधि बढ़ाकर हर इच्छुक विधायक को पूरा अवसर मिलना चाहिए। कम से कम से 10 मिनट का समय चाहिए। हम काफी चीजें नोट करके लेकर आए थे, लेकिन इतना समय नहीं मिला कि सभी बातों को सदन पटल पर रखा जा सके।

श्री लक्ष्मण नापा, रतिया

अच्छी शुरुआत है। नए को मौका मिलता है। सरकार का अच्छा कदम है। इसका समय बढ़ाया जा सकता है। एक घंटा की बजाए इसे डेढ़ घंटे तक किया जा सकता है, ताकि अधिक से अधिक माननीय विधायकों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री नीरज शर्मा, फरीदाबाद एनआईटी

हर विधायक की बारी आनी चाहिए। हर किसी को कम से कम 5 मिनट का अवसर मिले। प्रथा बहुत अच्छी है। नया माध्यम है। ऐसा भी हो सकता है कि जो विधायक किसी सत्र में नहीं बोल पाते, उन्हें अगले सत्र में प्राथमिकता के आधार पर समय मिलना चाहिए।

श्री घनश्याम दास अरोड़ा, यमुनानगर

जितना समय चाहते हैं, उतना समय नहीं मिल पाता। ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि पूरे सत्र में एक ही बार बारी आए। अभी तक विधायक को बोलने का अवसर अभिभाषण व बजट पर चर्चा के दौरान और प्रश्नकाल में ही मिलता था। शून्यकाल' से एक और विकल्प बन गया है।

श्री रणधीर गोलन, पुंडरी

मेरे जैसे नये विधायकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला है। 'शून्यकाल' की शुरुआत करके माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने सराहनीय कार्य किया है। इस दौरान बोलने का समय 7-8 मिनट होना चाहिए, तभी विधायक अपनी बात ठीक ढंग से रख सकेंगे।

3 दिन के सत्र में 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान आयोजित कुल तीन बैठकों में 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्यवाही का हिस्सा बने। पहले दिन एक तथा दूसरे और तीसरे दिन 2-2 प्रस्ताव शामिल किए गए। इनका विवरण इस प्रकार है:-

लंबित नलकूप कनैक्शन

1 सत्र के पहले दिन विधायक श्री वरुण चौधरी की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने लंबित नलकूप कनैक्शन को जारी करने से संबंधित मामला सदन में उठाया। इससे पहले माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्हें इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-30, जिसकी सूचना विधायक श्री मेवा सिंह तथा डॉ. बिशन लाल से भी प्राप्त हुई थी, जिसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-7 के साथ क्लब कर दिया गया है। वे भी अपने अनुपूरक पूछ सकते हैं। इसके बाद श्री वरुण चौधरी ने अपनी सूचना पढ़ी और संबंधित मंत्री ने वक्तव्य पढ़ा।

2 विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें

अध्यक्ष महोदय ने 23 अगस्त को सदन को सूचित किया कि उन्हें कक्षा प्रथम से आठवीं तक के लाखों विद्यार्थियों को विद्यालय की पुस्तकें उपलब्ध न करवाने से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-8 प्राप्त हुआ। यह प्रस्ताव भी विधायक श्री वरुण चौधरी द्वारा पेश किया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया।

3 भिवानी जिले में पेयजल किल्लत

विधायक श्रीमती किरण चौधरी की ओर से भिवानी जिले में पीने के पानी की भारी कमी से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने कहा कि तोशाम हलके के कई गांवों तथा भिवानी शहर की कुछ कॉलोनियों में पीने के पानी की भारी कमी है तथा मांग की कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। इसके बाद श्रीमती किरण चौधरी तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के बीच इस मुद्दे पर बहस हो गई। कुछ चर्चा के पश्चात, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूरे मामले की जांच के लिए श्री देवेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की देखरेख में समिति गठित होगी तथा समिति 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

5 विवि में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति

विधायक श्री भारत भूषण बतरा, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री वरुण चौधरी तथा डॉ. बिशन लाल द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही साथ हरियाणा के केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर ऑनलाइन स्थानांतरण की नीति की कमियों से संबंधित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 18 पेश की गई। अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्रीमती गीता भुक्कल तथा 3 अन्य विधायकों श्री भारत भूषण बतरा, श्री अमित सिहाग तथा श्री आफताब अहमद) द्वारा भी समान विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-18 के साथ क्लब कर दिया गया है, अतः दो अन्य हस्ताक्षरी विधायकों को अनुपूरक उठाने का अवसर दिया गया। श्री भारत भूषण बतरा द्वारा सूचना पढ़ने के बाद सहकारिता मंत्री ने वक्तव्य दिया।

4 पेपर लीक पर अनेक प्रस्ताव समायोजित

24 अगस्त को पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रश्नपत्र एवं उत्तर कुंजी लीक होने पर केंद्रित रहा। यह प्रस्ताव महम से विधायक श्री बलराज कुंडू की ओर से लाया गया। विधायक किरण चौधरी तथा श्री शमशेर सिंह गोगी ने भी इस विषय से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना दी थी। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने इन सभी को क्लब कर श्री बलराज कुंडू को बात रखने की अनुमति दी। श्री कुंडू ने कहा कि 7 अगस्त, 2021 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई पुलिस सिपाही की परीक्षा को इसके चलते रद्द किया गया है। इस विषय पर श्रीमती किरण चौधरी तथा श्री शमशेर सिंह गोगी की तरफ से भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। इसलिए उन्हें भी अनुपूरक प्रश्न उठाने का अवसर दिया गया। विधायक श्री भारत भूषण बत्तरा, श्री आफताब अहमद, राव दान सिंह, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री वरुण चौधरी तथा श्री अमित सिहाग द्वारा भी समान विषय पर स्थगन प्रस्ताव संख्या-1 की सूचना दी गई थी। जिन्हें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-36 में बदल गया गया और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-5 के साथ क्लब कर दिया गया है, प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते श्री भारत भूषण बतरा तथा 2 अन्य हस्ताक्षरी को अनुपूरक पूछने की अनुमति मिली। इसके साथ ही विधायक श्री जगबीर सिंह मलिक द्वारा भी समान विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 की सूचना प्राप्त हुई थी, जो कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या संख्या-37 में बदल दी गई है तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-5 के साथ क्लब कर दिया गया है। इन प्रस्तावों पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया तथा मुख्यमंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट की। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पेपर लीक मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने की मांग की तथा वॉक आऊट भी किया। ■

मानसून सत्र- 2021 में पारित किए गए विधेयकों का विवरण

1. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2021
2. महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधेयक, 2021
3. हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021
4. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021
5. पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2021
6. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021
7. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021
8. हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021
9. हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021
10. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधयेक, 2021
11. हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021

विधान सभा सचिवालय में प्रश्नकाल के ड्रा निकलवाते विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री रणबीर सिंह गंगवा, कांग्रेस विधायक श्री वरुण चौधरी, विधान सभा सचिव श्री राजेंद्र नांदल और दूसरे अधिकारी।

सरकार ने पेश किए 11 विधेयक

विधान सभा सचिवालय को सरकार की ओर से 11 विधेयक पेश करने के नोटिस प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही 2 प्राइवेट मेंबर बिल और 9 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के नोटिस भी आए। सरकार की ओर से जो विधेयक पेश किए जाने हैं, इनमें से पहला शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित है, जिसे संबंधित मंत्री ने पेश किया गया। इसके साथ ही महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक भी पेश किया गया। हरियाणा लोकायुक्त विधेयक में संशोधन के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 भी मानसून सत्र का हिस्सा बना। वहीं विधायक श्री राकेश दौलताबाद और श्री आफताब अहमद की ओर से प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने संबंधित नोटिस प्राप्त हुए थे।

विधानसभा अध्यक्ष की प्रश्नकाल को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाने की मुहिम

सचिवालय को प्राप्त हुए 238 तारांकित और 120 अतारांकित प्रश्नों के लिए नोटिस

विधान सभा के 20 अगस्त से शुरू हुए मानसून सत्र के लिए प्रश्नकाल में प्रश्नों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी करने के लिए विस अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा शुरू की गई व्यवस्था के तहत 13 अगस्त को मानसून सत्र के पहले तीन दिनों के लिए ड्रा निकाले गए।

इस दौरान तारांकित प्रश्नों के लिए 60 विधायकों के नामों की पर्चियां निकाली गई। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री रणबीर सिंह गंगवा, कांग्रेस विधायक श्री वरुण चौधरी, विधान सभा सचिव श्री राजेंद्र नांदल तथा विधान सभा के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विधान सभा की परंपरा के अनुसार सत्र के दौरान दिन का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रहता है। इस दौरान विधायक सदन में अपने प्रश्नों को रखते हैं और सरकार की ओर से संबंधित मंत्री उसका जवाब देते हैं।

विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता इस प्रश्नकाल की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए उन्होंने ड्रा से प्रश्नों का चयन करने की परंपरा शुरू की है। इससे पूर्व विधान सभा अध्यक्षों पर सत्ता पक्ष के विधायकों के ज्यादा प्रश्न शामिल करने के आरोप लगते रहे हैं। नई व्यवस्था में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों की उपस्थिति में ड्रा निकाला जाता है। ■

- नौ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और ग्यारह विधेयक पेश करने के नोटिस प्राप्त
- दो विधायकों की तरफ से मिली प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की सूचना

हरियाणा की 14वीं विधान सभा के मानसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार, 20 अगस्त 2021 को पूछे गए तारांकित प्रश्न

श्री वरुण चौधरी, मुलाना

परीक्षण प्रयोगशाला कब बनेगी

क्या खाद्य एवं औषधीय मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्म सिंह छौक्कर, समालखा

आईटीआई का निर्माण कब होगा

क्या कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मन्त्री कृपया बताएंगे कि समालखा के गांव चिलकाना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

श्रीमती सीमा त्रिखा, बड़खल

ईको ग्रीन को कितनी रकम जमा

ईको ग्रीन कम्पनी को जमा की राशि का ब्यौरा क्या है। सरकार व फरीदाबाद को कितना लाभ हुआ? कंपनी शर्तें मानती है क्या? थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर की संख्या भी बताएं। कम्पनी फीस की रसीद देती है क्या?

श्री जगबीर सिंह मलिक, गोहाना

कोविड केन्द्रों का ब्यौरा दें

राज्य में कोविड केन्द्रों में मृतकों का ब्यौरा क्या है; यहां नियुक्त चिकित्सकों, पैरा मैडिकल स्टाफ तथा अन्य स्टाफ का ब्यौरा भी दें। इनमें से कितने कर्मचारियों की कोविड से मौत हुई? क्या इन्हें दोगुना वेतन मिला है?

श्री सीता राम यादव, अटेली

सड़कें चारमार्गी होंगी क्या

क्या अटेली हलके में इन सड़कों को चारमार्गी बनाने का प्रस्ताव है: अटेली से महेन्द्रगढ़; भडफ से उन्हानी दादरी मोड़ तक; कनीना से कांटी-खेड़ी; मोहनपुर नांगल से झिंगावन, महेन्द्रगढ़ रोड; उन्हानी टी प्वाईंट से धनौन्दा, बाघोत।

श्री नीरज शर्मा, फरीदाबाद एनआईटी

पीपीपी योजना का डाटा दें

परिवार पहचान पत्र योजना के तहत कितने परिवार पंजीकृत हैं। व्यक्तियों की संख्या भी बताएं। प्रति व्यक्ति तथा प्रति परिवार आय क्या है; इस डाटा को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री भारत भूषण बतरा, रोहतक
श्री जगबीर सिंह मलिक, गोहाना

किसानों के खिलाफ कितने केस?

कृषि बिलों के विरुद्ध आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ पंजीकृत की गई एफआईआर का जिलावार ब्यौरा क्या है; राजद्रोह की कितनी एफआईआर हैं। इनका आधार क्या है?

श्रीमती रेणू बाला, सढ़ौरा

शहीदी स्मारक तथा स्वागत द्वार का निर्माण

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि उनकी घोषणा के बावजूद रामगढ़ के शहीद रौकी की स्मृति में शहीदी स्मारक तथा स्वागत द्वार का निर्माण न करने के कारण क्या हैं?

श्री बलराज कुण्डू, महम

पेट्रोल पर टैक्स कम होगा क्या

क्या उप मुख्यमंत्री मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में डीजल/पेट्रोल पर टैक्स कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रीमती किरण चौधरी, तोशाम

पशु मेलों का शुल्क बताएं

पशु मेलों के लिए प्रवेश शुल्क 10 से 1000 रुपये कर दिया है क्या? इनमें पशुओं की बिक्री/खरीद पर 4 फीसदी कर भी लगाया है क्या? निजी खिलाड़ियों को मेले आयोजित करने की अनुमति दी है क्या?

श्री आफताब अहमद, नूंह

कोरोना से मौतों का ब्यौरा चाहिए

राज्य में इस साल 24 मार्च से 31 जुलाई तक कोरोना से कितनी मौतें हुई; ऑक्सीजन की कमी से कितनी जान गई। मृतकों के परिजनों व चिकित्सीय स्टाफ को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा भी दें।

श्री राम कुमार गौतम, नारनौंद

पंचकूला के सैक्टर का ब्यौरा दें

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पंचकूला का सेक्टर-24 कब जारी किया था; तब इस सेक्टर का योजनाबद्ध किया गया क्षेत्र तथा बिक्री योग्य क्षेत्र क्या था? क्या प्लाट धारकों से बढ़ी राशी मांगी गई है?

श्री अमरजीत ढांडा, जुलाना

जल भराव की समस्या सुलझाना

क्या जुलाना के गांव लजवाना खुर्द, सिरसा खेड़ी, मेहरड़ा, लजवाना कलां, कालगढ़, हथवाला तथा पाली में जलभराव की समस्या है; यहां ड्रेन का निर्माण तथा इसे पाली पम्प हाउस से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है क्या?

डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा, जींद

पेयजल परियोजना कब पूरी होगी

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जींद शहर में पीने के पानी की परियोजना के पूरे किए गए चरणों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

श्री असीम गोयल, अम्बाला शहर

पीने के पानी की भूमिगत पाइप लाइनें बिछाना

क्या अम्बाला शहर निर्वाचनक्षेत्र में अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाने का कार्य जो कि वर्ष 2017 में स्वीकृत/आरम्भ हुआ था, पूरा हो गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री सुभाष गांगोली, सफीदों

ढाणियां एकीकृत कब होंगी

क्या यह तथ्य है कि सफीदों के आसपास की ढाणियां न तो किसी ग्राम पंचायत और न ही नगर परिषद् के साथ जुड़ीं हैं; इन्हें पंचायतों या नगर परिषद से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है क्या?

श्री असीम गोयल, अम्बाला शहर

बरसाती पानी की निकासी करना

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या वर्ष 2017 के पश्चात अम्बाला शहर निर्वाचनक्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी करने के लिए क्या पग उठाए गए तथा उसका ब्यौरा क्या है?

श्री अमरजीत ढांडा, जुलाना

व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना

क्या यह तथ्य है कि जुलाना के गांव पाली, मेहरड़ा, गतौली, शामलो, करेला में स्थित पम्प हाउस में सामान्य बिजली कनेक्शन दिए गए हैं; यदि हां, तो क्या इन पम्प हाउस को व्यक्तिगत कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव है?

श्री बलराज कुण्डू, महम

रोजगार उपलब्ध करवाना

क्या यह तथ्य है कि सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है तथा पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा प्रथम स्थान पर है? यदि हां, तो इससे निजात पाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है क्या?

श्रीमती सीमा त्रिखा, बड़खल

रेनी वेल योजना का ब्यौरा

जिला फरीदाबाद के लिए सरकार की रेनी वेल योजना का ब्यौरा क्या है; इसके तहत बिछाई गई पाइप लाईनों का ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। बड़खल के जल बुस्टरों में सुधार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है क्या?

21 सितम्बर 2021 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात करते हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

प्रदेश सरकार, केंद्र और लोक सभा अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद श्री अमित शाह से मिले विधान सभा अध्यक्ष

हरियाणा को चाहिए नई विधान सभा

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने सदन की कार्यवाही और सचिवालय के काम में आड़े आ रही जगह की कमी का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्री गुप्ता ने संसद भवन और नवगठित राज्यों के आधुनिक विधान भवनों की तर्ज पर हरियाणा के लिए भी भव्य विधान भवन की मांग की है। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ-साथ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है।

इसके बाद हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने 21 सितम्बर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान श्री गुप्ता ने वर्तमान विधान भवन और पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की हिस्सेदारी और नई विधान सभा बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जगह दिलाने की मांग की। श्री शाह ने विस अध्यक्ष को तीनों मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। श्री गुप्ता ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ यूटी प्रशासक के साथ हुए पत्राचार और विधान सभा सचिवालय के पास उपलब्ध इन मसलों से जुड़े तथ्यों को भी गृह मंत्री के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि विधानपालिका की गरिमा और आधुनिक दौर की कार्यशैली के लिए नया विधान भवन समय की आवश्यकता बन चुका है। नए परिसीमन में हरियाणा में विधायकों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा सदन में 90 विधायकों के लिए ही स्थान उपलब्ध है। इसके साथ ही संसदीय कामकाज के तौर-तरीकों में भी बड़े परिवर्तन का दौर चल रहा है। ऐसे में भव्य और आधुनिक विधान भवन बनाना जरूरी हो गया है।

उन्होंने कहा है कि बदलते दौर में संसदीय कार्य का स्वरूप बदल रहा है। इसके लिए न सिर्फ पर्याप्त स्थान चाहिए बल्कि आधुनिक तकनीक से लेस संचार ढांचा भी वक्त की जरूरत बन चुका है। इसलिए प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन से नए विधान भवन के लिए जगह की मांग करनी चाहिए। योजना में विपक्ष को साझीदार बनाने के लिए पत्र की प्रति विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भेजी गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय और लोक सभा अध्यक्ष को 28 जून को लिखे पत्र में श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि राज्य के अस्तित्व में आने के करीब 55 साल बाद भी हरियाणा विधानसभा स्थान अभाव का दंश झेल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब से बंटवारे के वक्त हुए समझौते के अनुसार हरियाणा को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल पाया है। दोनों प्रांतों का एक ही विधान भवन होने के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।

देश के दूसरे राज्यों की मिसाल देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि सभी राज्यों और कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों के पास स्वतंत्र विधान भवन है। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलगाना, उत्तराखंड और इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण है, जहां पहले से विधानसभा भवन की इमारत होने बावजूद समय की मांग के अनुसार नवनिर्माण किए गए। राजस्थान विधानसभा का नवनिर्मित विधानभवन जयपुर में, गुजरात विधानसभा का गांधी नगर में, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला स्थित विधान भवन इसके प्रमुख उदाहरण है। इतना ही नहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी आवश्यकताओं के अनुसार नया संसद भवन बनाया जा रहा है। ■

मीडिया का बदला स्वरूप, अब चाहिए बड़ी हाईटेक व्यवस्था

प्रदेश, केंद्र और लोक सभा को लिखे पत्र में विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने वर्तमान दौर में मीडिया के बदलते स्वरूप और आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक सुविधाओं से लेस व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा प्रदेश और इसकी विधान सभा का गठन हुआ था, तब मीडिया का स्वरूप इतना बड़ा नहीं था। इसलिए प्रेस गैलरी समेत अनेक व्यवस्था उस समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई थी। अब तकनीकी विकास के कारण इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अब प्रिंट मीडिया के साथ–साथ इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया ने भी समाज में विशिष्ट स्थान बनाया है। इसके मद्देनजर नए प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करना समय की जरूरत बन चुकी है।

किसान आंदोलन जुड़ी गतिविधियों और हरियाणा के सामाजिक, राजनीति मसलों पर चर्चा

श्री गुप्ता ने लोकसभा अध्यक्ष से की विधायी कामकाज पर चर्चा

नई दिल्ली में लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट करते हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने 19 जुलाई को नई दिल्ली पहुंच लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से मुलाकात की।

इस दौरान दोनों पीठासीन अधिकारियों के बीच विधायी कामकाज को लेकर चर्चा हुई।

श्री गुप्ता ने हरियाणा विधान सभा में किए जा रहे अभिनव प्रयोगों की जानकारी भी लोक सभा अध्यक्ष को दी। इस दौरान हरियाणा विधान सभा के डिजीटलाइजेशन पर बात हुई। श्री गुप्ता ने बताया कि हरियाणा विधान सभा में मानसून सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई है। ■

नई दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट करते विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

केंद्रीय मंत्री से भी मिले विधानसभा अध्यक्ष

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने 18 जुलाई को देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंच हाल ही में मोदी मंत्रीमंडल का हिस्सा बने श्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री ने श्री भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने उन्हें नए दायित्व की बधाई तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन जुड़ी गतिविधियों और हरियाणा के सामाजिक, राजनीति मसलों पर भी चर्चा हुई। ■

साक्षात्कार **श्री दुष्यंत चौटाला,** उपमुख्यमंत्री

सबसे कम उम्र के उपमुख्यमंत्री

इतिहास में सबसे युवा सांसद बनने का भी रिकॉर्ड

श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा राज्य के सबसे कम उम्र के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के सह-संस्थापक भी हैं। भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। वह वर्ष 2014 में हिसार से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। एक गतिशील युवा नेता के रूप में श्री दुष्यंत चौटाला सक्रिय सांसद रहे, जिसके चलते उनका संसदीय प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक प्रश्न उठाए और 230 से अधिक बहसों में भाग लिया, जो कि राष्ट्रीय औसत 63.6 से कहीं अधिक है। इस दौरान उन्होंने 21 निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए। श्री चौटाला ने संसद की कई समितियों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह वाणिज्य पर स्थायी समिति, शहरी विकास पर स्थायी समिति, मेज पर रखे गए पत्रों पर समिति और अनुमान समिति के सदस्य और सलाहकार समिति, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सदस्य थे। श्री दुष्यंत चौटाला ने यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीएससी की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से एलएलएम और हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जन-संचार में एमए की। सदन संदेश के प्रधान संपादक दिनेश कुमार से उनकी हरियाणा के विकास और इसके भविष्य को लेकर विस्तृत बातचीत हुई है। प्रस्तुत है इस बातचीत के प्रमुख अंशः-

प्रश्न: मात्र 26 साल की उम्र में सांसद बनकर संसदीय इतिहास का रिकॉर्ड आपके नाम है। आप युवाओं के आइकॉन बने हैं। आज के युवा की दशा को कहां आंकते हैं?

जवाब: देश बदल रहा है और धीरे-धीरे प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं का जोश और उनका नेतृत्व देखने को मिल रहा है। मेरे लिए भी यह जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव रहा है, जहां शिक्षा छोड़ कर राजनीति में आना पड़ा, लेकिन मैंने इसे क्राइसिस परिस्थिति न मानते हुए अवसर बनाया। जब मैं विधान सभा में चुन कर आया और उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली तो लोकसभा का अनुभव काम आया। इसी का परिणाम है कि प्रदेश को विकास की रफ्तार पर चला पा रहे हैं। हर युवा को चुनौती स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

प्रश्न: आज का युवा काफी मेहनत करता है। कहीं यह मेहनत सिर्फ कैरियर केंद्रित होकर तो नहीं रह गई।

जवाब: वर्तमान का युवा प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। परिवार तक सीमित रहने वाले और अवसर ढूंढ़ कर आगे बढ़ने वाले युवाओं में बड़ा अंतर है। हर क्षेत्र में ऐसा देखने को मिल रहा है। खेल के क्षेत्र में तो कमाल ही कर रखा है। हॉकी की लड़कियां की टीम में 7 लड़कियां हरियाणा की हैं और ये सब उस आयुवर्ग की है, जिसमें कभी शादी करने की सोच लेते थे। आज नीरज चौपड़ा और रवि ने प्रदेश का नाम रोशन किया। बिजनेस के क्षेत्र को देख लीजिए। कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र हरियाणा के युवाओं से अछूता नहीं है। यह अभिभावकों पर भी निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कितना प्रेरित कर पाते हैं।

प्रश्न: वर्तमान में युवाओं को विचार दर्शन से कितना जुड़ा देखते हैं। कहीं वैचारिक शून्यता का वातावरण तो नहीं बन रहा? परिवार से आगे की दुनिया को लेकर युवा कितना वास्ता रखते हैं?

जवाब: समय के साथ भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक परिवेश में भी दृष्टिकोण बदल रहा है। कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला या कहें कि ईसाई प्रभुत्व वाला देश रूस जार के अत्याचारों से तंग आकर उनकी विचारधारा को तिलांजलि दे चुका है। चीन, कोरिया भी बदल रहे हैं। दुनिया के सभी देशों में नेतृत्व बदलाव के साथ-साथ वैचारिक परिवर्तन आए हैं। तकनीकी विकास के कारण भी परिवेश बदल रहा है। आज से 20 वर्ष बाद शायद राजनीति करने के तौर तरीके भी बदल जाएंगे। कुछ वर्ष पहले तक विधायक, सांसद डायरी और थैला लेकर चलते थे, लेकिन आज आईपैड में उनसे कहीं ज्यादा डाटा लेकर चल सकते हैं। आने वाले वक्त में शायद मोबाइल ही यह काम कर दें और आईपैड की जरूरत भी कम हो जाएगी।

प्रश्न: हरियाणा सरकार में 10 प्रमुख विभागों में श्रम और रोजगार विभाग भी आपके पास है। रोजगार की दृष्टि से हरियाणा कहां खड़ा हैं?

जवाब: कोरोना महामारी से समूचा विश्व प्रभावित हुआ, लेकिन हरियाणा ने इस दौरान जो रणनीति तैयार की उसके कारण नुकसान कम से कम संभव हो सका। हमने औद्योगिक मजदूरों का पलायन रोका। जो चले गए थे, वे भी वापस आए और हमारे उद्योगों को गति प्रदान की। इसका परिणाम यह रहा कि हरियाणा में वर्ष 2019-20 में से ज्यादा राजस्व 2020-21 में हुआ। गत वर्ष फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने हरियाणा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। एशिया का सबसे बड़ा वेयरहाउस मानेसर के पट्टी हाजिपुर गांव में बन रहा है। 140 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट से 7500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्माल बैटरी कंपनी एटीएल ने मेवात के गांव रोजका मेव में 180 एकड़ ली है। यहां बैटरी निर्माण का प्लांट शुरू हो चुका है। इससे 3 हजार युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खरखौदा में 900 एकड़ भूमि पर मारूति का प्लांट लगेगा। इसमें 800 एकड़ में कार और 100 एकड़ में सुजुकी बाइक की यूनिट लगेगी। यहां गुरुग्राम के प्लांट से 5 गुणा ज्यादा निर्माण होगा।

खेलों में है खास दिलचस्पी, नेत्रदान में विश्व रिकॉर्ड

श्री दुष्यंत चौटाला ने 'पार्लियामेंटेरियन ग्रुप फॉर चिल्ड्रन एंड वॉश फॉर्म' के सह-संयोजक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 2015 में टोक्यो में आयोजित 'युवा सांसदों के आईपीयू वैश्विक सम्मेलन' में भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेलों के प्रति उनका विशेष रुझान रहा है। उन्हें 2017 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह 'साउथ एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन' और 'कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन' के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। वह भारतीय ओलंपिक संघ के एक मान्यता प्राप्त सदस्य हैं। वह 'जन नायक चौधरी देवी लाल विद्यापीठ' के उपाध्यक्ष रहे और उनके कुशल मार्गदर्शन में 10,458 नेत्रों के लिए पंजीकरण हुआ। एक बार में इतने बड़े स्तर पर नेत्रदान का यह विश्व रिकॉर्ड है।

प्रश्न: राजस्व किसी भी सरकार की रीढ़ की तरह होता है। यह विभाग भी आप संभालते हैं। करीब दो वर्ष से तालाबंदी की मार अर्थव्यवस्था झेल रही है। अब हालात कैसे हैं?

जवाब: आपको सुन कर हैरानी होगी कि कोविड महामारी के बावजूद हमारी आमदनी बढ़ी है। धारा 7ए लागू होने के बावजूद लोग एनओसी लेकर बड़े प्लॉटों की रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि विकास की रफ्तार बढ़ रही है। यह सब विकासशील सोच के कारण संभव हो सका है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करना भी ऐसा ही प्रयास है, जिसे बाद में प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लागू किया। 8 राज्य स्वामित्व नाम से इस योजना का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसी कारगर योजना बनाने वाला हरियाणा दुनिया का पहला राज्य है। फिलहाल थ्री डी मैपिंग, डिजीटली मैपिंग, ड्रोन इमेजिंग और लट्ठा आधारित मैपिंग को एक साथ समन्वित कर प्रदेश का समस्त राजस्व रिकॉर्ड आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की है।

प्रश्न: आबकारी और कराधान विभाग की आमदनी भी बढ़ी है, जिससे आर्थिक स्थित मजबूत हुई है, कहीं सामाजिक दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

जवाब: हम अपने राजस्व को 6200 करोड़ से 6600 करोड़ और अब 6600 करोड़ से 7500 करोड़ रुपये पर ले आए हैं तो इसमें सामाजिक दुष्प्रभाव की तो बात ही नहीं है। यह लीकेज और चोरी बंद करने से संभव हो पाया है। हमने व्यवस्थागत सुधार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की आर्थिक हालात में काफी सुधार हुआ है।

गांधी जी कहते थे कि प्रत्येक गांव में एक गणराज्य के सभी गुण होने चाहिए, जिसमें स्वावलम्बन, स्वशासन आवश्यकतानुसार स्वतंत्रता और विकेन्द्रीकरण तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सभी अधिकार पंचायत के पास हों। स्वतंत्रता का 75वां साल मनाने जा रहे हैं। पंचायतों को इस दिशा में कितना विकसित देखते हैं? गांवों की स्वायत्तता बढ़ाई है। पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के लिए बजट का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। 'ग्रामीण सरकारों' को सुदृढ़ किया है। अब ग्राम सचिवालय की संकल्पना साकार करने जा रहे हैं। वहां सरपंच, पंचों के बैठने की जगह, पुस्तकालय और सीएचसी सेंटर स्थापित होंगे। ये केंद्र गांव की योजना और विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी होंगे। हरियाणा

की पंचायती राज व्यवस्था में सेंटर फॉर एक्सीलेंस और रूरल एंड एडवांस इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित होंगे।

प्रश्न: लाल डोरा मुक्ति की देश भर में सराहना हुई है। ऐसा विचार कहां से आया?

जवाब: एक बैठक में इस पर चर्चा हुई। उसके बाद सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से इस बारे में बात हुई। इस विभाग को शामिल किया। उनकी टीम ने यहां आकर मैपिंग की और हरियाणा के विजिन को सिरे चढ़ाया। सबसे पहले 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले का गांव सिरसी का रिकॉर्ड डिजीटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया। उसी दिन से हरियाणा के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य ले लिया था।

प्रश्न: प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके बाद रोजगार प्रदाता प्रतिष्ठानों का रुख कैसा रहा?

जवाब: देखिए, भ्रम बहुत फैलाए गए, लेकिन हमने कंपनियों से बात की है। इसके परिणामस्वरूप में हरियाणा में 3000 करोड़ रुपये की जमीन खरीद कर 12000 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इन कंपनियों को पता है कि हमारी सरकार कुशल मानव शक्ति देने में पूरी तरह से सक्षम है। कौशल विकास के बलबूते पर ही कंपनियों को 75 फीसदी युवा देंगे।

प्रश्न: रोजगार विभाग की 'सक्षम' योजना को लेकर कुछ नकारात्मक खबरें छपी हैं। कितनी सख्ती से निपटेंगे?

जवाब: डिजीटलाइजेशन के फायदों के साथ-साथ कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। डिजीटलाइजेशन से ही सरकार ने गरीबों को मिलने वाले सरसों के तेल के लिए 250 रुपये प्रति परिवार डीबीटी किया। अब इसका कुछ नुकसान भी हुआ कि हमारे प्रदेश के काफी लोगों ने अपने राशन कार्ड के साथ बैंक खातों को नहीं जुड़वाया, जिस कारण से कुछ लोग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए।

जल्द ही हरियाणा के 10 लाख बैंक खाते आधार के साथ लिंक होंगे, जो अपने आप में ऐतिहासिक कदम होगा। कुछ कमियों के चलते ऐसे भी मामले आए हैं कि बुढ़ापा पैंशन तक भी किसी और के खाते में गई है। इसके लिए नागरिकों को जागरूक रह कर प्रयास करने होंगे। तभी सरकारी योजनाओं का भी सही ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा।

प्रश्न: जननायक जनता पार्टी अपेक्षाकृत नई पार्टी है। इसका वैचारिक अधिष्ठान क्या है?

जवाब: जननायक जनता पार्टी बेशक नया दल है, लेकिन इसका वैचारिक अधिष्ठान काफी पुराना है। यह चौ. देवी लाल जी के दिखाए रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। इसी का परिणाम है कि गत पौने दो वर्षों में हमने जितने भी निर्णय लिए उन सबमें चौ. देवी लाल जी की विचारधारा साफ झलकती है। रोजगार के क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को तवज्जो देने की बात हो, बुढ़ापा पैंशन 2500 रुपये तक की गई। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व हो या पिछड़ा वर्ग ए को 8 फीसदी आरक्षण दिया गया।

वर्तमान सरकार की ओर से लिया गया एक भी निर्णय ऐसा नहीं है, जो पूंजीपतियों के पक्ष में हो। 'हरियाणा इंटरप्राइजिज एंड इम्पलाइमेंट पॉलिसी-2020 (एचईईपी) हरियाणा को आर्थिक रूप से गति देने वाली साबित हो रही है। इससे हरियाणा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बने हैं। इस पॉलिसी में प्रावधान है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को 48 हजार प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष सब्सिडी दी जाएगी।

प्रश्न: ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 'एक ब्लॉक-एक उत्पाद' योजना का क्या भविष्य देखते हैं?

जवाब: ग्रामीण परिवेश के शिल्पकारों और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए यह विशेष योजना है। राज्य सरकार की योजना राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टिकोण से जोड़ने की है। पिछले एक साल में एमएसएमई के तहत लागू की जा रही हरियाणा की 'एक जिला, एक उत्पाद% योजना पूरे देश में एक मॉडल के रूप में सामने आई है। अब सरकार प्रदेश के 137 प्रखंडों में पदमा नाम से 'वन ब्लॉक, वन प्रोडक्ट' योजना शुरू की जा रही है, जिसमें क्लस्टर में ही आम सेवायें, प्रयोगशाला परीक्षण, पैकेजिंग, परिवहन, लेखा जोखा आदि की व्यवस्था होगी। खंड स्तर पर बड़ी उपयोगी रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे अकेले नरवाना ब्लॉक में चमड़े की जूती बनाने की 300 लघु ईकाइयां हैं। कई क्षेत्रों में हमारे स्वयं सहायता समूह बाजरे के बिस्कुट, मट्ठी बनाते हैं।

फरीदाबाद की एक एमएसएमई सैन्य वाहन बनाती है, जो जम्मू-कश्मीर में काम आते हैं। ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे ये एक ब्रांड के तौर पर विकसित हो सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे उद्यमी, बड़े उद्योगों से मुकाबला कर सकने की स्थिति में होंगे। सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। ■

कानूनी राय लेने के बाद विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने की घोषणा

प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने 20 मई को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कालका से कांग्रेस विधायक श्री प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल कर दी है। चौधरी की सदस्यता बहाली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा पर स्टे लगाने के मद्देनजर की गई है तथा इस पर अंतिम फैसला सोलन जिला एवं सत्र न्यायालय में निर्णय पर निर्भर करेगा।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ स्थित प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्री जितेंद्र कुमार की अदालत ने गत इसी वर्ष 14 जनवरी को एक आपराधिक मामले में श्री प्रदीप चौधरी को दोषी करार दिया था। अदालत ने उन्हें लोगों को भड़काने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाया है। 28 जनवरी को उन्हें 3 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। नालागढ़ अदालत के फैसले के मद्देनजर हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की थी। विधान सभा सचिवालय ने कालका विधान सभा सीट को रिक्त घोषित कर इसकी जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी थी। निचली अदालत द्वारा सुनाई सजा के खिलाफ श्री प्रदीप चौधरी ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को निचली अदालत के सजा संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश में कहा गया है कि जब तक उनकी आपराधिक अपील जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित है तब तक उनकी सजा पर रोक रहेगी। इस फैसले के मद्देनजर हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रदीप चौधरी की विधान सभा सदस्यता से अयोग्यता और कालका निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त करने की अधिसूचना 19 अप्रैल 2021 से जिला एवं सत्र न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक वापस ली है। लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) में प्रावधान है कि किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि दो वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से आयोग्य माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किये जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य माना जाता है। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस की सुनवाई करते वक्त भी इसे स्पष्ट किया है। ■

हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे पर विपक्ष ने जताई थी आपत्ति

दशकों बाद विधान सभा में बनी प्रवर समिति

हरियाणा विधान सभा में एक विधेयक के मसौदे पर विपक्ष के संशयों को दूर करने के लिए करीब तीन दशक बाद प्रवर समिति का गठन किया गया है। विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता की पहल पर हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम क्रमांक 132 के तहत गठित इस समिति में प्रदेश के तीनों प्रमुख दल भाजपा, कांग्रेस और जजपा के सदस्य शामिल किए गए हैं।

मामला हरियाणा खेल विश्वविद्यालय अधिनियम से जुड़ा है। हरियाणा विधान सभा ने यह अधिनियम 6 अगस्त 2019 को पारित किया था। सदन से पारित होने के बाद विधेयक महामहिम राज्यपाल की अनुमति के लिए राजभवन भेजा गया। महामहिम राज्यपाल ने इस विधेयक पर टिप्पणी की, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने विधेयक को वापस लेने के लिए 8 मार्च 2021 विधान सभा में प्रस्ताव पास करवाया।

राज्यपाल की टिप्पणियों का पालन करते हुए सरकार ने 17 मार्च 2021 को नए सिरे से विधेयक का मसौदा सदन पटल पर रखा, जिस पर अगले दिन अर्थात 18 मार्च 2021 चर्चा हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य विपक्षी सदस्यों ने इस बिल पर कुछ आपत्तियां जताई थीं।

विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने उनकी आपत्तियों के निवारण के लिए सदन की राय जाननी चाही। सदन में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि बिल प्रवर समिति को भेजा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि तीनों बड़े दल अपनी-अपनी पार्टी के सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय को भेज देंगे, ताकि प्रवर समिति का गठन किया जा सके। अब तीनों राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी से सदस्यों की सूची प्राप्त विधान सभा अध्यक्ष को प्राप्त हो गई हैं। इसके आधार पर विस अध्यक्ष ने प्रवर समिति का गठन कर दिया है।

प्रवर समिति में सबंधित विभाग के मंत्री बतौर इंचार्ज बिल, विधान सभा उपाध्यक्ष और एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से एक सदस्य को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। अब इस समिति में विधान सभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा, खेल मंत्री श्री संदीप सिंह, विधायक श्री अभय सिंह यादव, श्री असीम गोयल, श्री हरविंदर कल्याण, श्री महिपाल ढांडा, श्री ईश्वर सिंह, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री भारत भूषण बतरा और श्री रणधीर सिंह गोलन शामिल हैं।

गौरतलब है कि इससे पूर्व 16 नवंबर 1973, 12 दिसंबर 1986 और नवंबर 1996 को भी विधेयकों के प्रारूप प्रवर समिति को भेजे गए थे। विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से किसी भी बिल का मसौदा सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाता है तो विपक्ष को उस पर अपनी राय प्रकट करने का पूरा अधिकार है। अगर विपक्ष को विधेयक के मसौदे पर कुछ खामियां नजर आती है तो उनका निवारण करना आवश्यक है। इन आशंकाओं का निवारण करने के लिए इस प्रवर समिति का गठन किया गया है। ■

समिति संसदीय परंपरा के मुताबिक बिल पर काम करेगी। इसीलिए इसमें सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के सदस्य भी शामिल किए गए हैं। आपत्तियों के निवारण के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी।
- श्री ज्ञान चंद गुप्ता, अध्यक्ष
हरियाणा विधान सभा

श्री रणबीर गंगवा
विधान सभा उपाध्यक्ष

श्री संदीप सिंह
खेल मंत्री

श्री ईश्वर सिंह,
गुहला

श्री अभय सिंह
यादव

श्री जगबीर सिंह
मलिक

श्री असीम
गोयल

श्रीमती गीता
भुक्कल

श्री महिपाल सिंह
ढांडा

श्री हरविंदर
कल्याण

श्री भारत भूषण
बतरा

श्री रणधीर सिंह
गोलन

लोक सभा अध्यक्ष ने की देशभर के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक

कोरोना से निपटने के लिए विधायी तंत्र सक्रिय

लोक सभा द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में अपनी बात रखते हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए देश का विधायी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहा। 19 अप्रैल को लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने देश के सभी विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रदेश के एनसीआर और जीटी रोड स्थिति जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताई।

श्री गुप्ता ने विधान सभा की ओर से किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा भी दिया। उन्होंने बताया विधान सभा सचिवालय जल्द ही नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा। यह कक्ष लोक सभा के माध्यम से सभी राज्यों के साथ समन्वय कर लोगों की सहायता और विकट परिस्थितियों से निपटने में मदद करेगा। इसके साथ ही हरियाणा विधान सभा सचिवालय टीकाकरण, लोगों को जागरूक करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसके लिए अनेक फैसले किए जा चुके हैं।

- श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने विधान सभा में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के दिए निर्देश
- लोगों को जागरूक करने में विस सचिवालय ने निभाई सक्रिय भूमिका

लोक सभा अध्यक्ष के प्रयास से आयोजित पीठासीन अधिकारियों की वर्चुअल बैठक में ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के पीछे दो प्रमुख कारक ध्यान में आ रहे हैं। पहला प्रदेश का दिल्ली से सटा होना और दूसरा जीटी रोड। हरियाणा का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आता है। प्रदेश के 22 में से 14 जिले एनसीआर का हिस्सा है। इन जिलों से बड़ी संख्या में लोगों का दिल्ली आना-जाना रहता है। इसके साथ ही उत्तर भारत के राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के लोग हरियाणा में स्थित जीटी रोड के माध्यम से दिल्ली आवागमन करते हैं। हरियाणा में इस बार कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर एनसीआर और जीटी रोड के साथ लगते जिलों में ही है।

गुप्ता ने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों से भी यहां करोना संक्रमण बढ़ने की आंशका है। दूसरे प्रदेशों से किसान एक्टिविस्ट भी यहां सक्रिय हैं। दिल्ली के आसपासर् दए जा धरने भी हरियाणा के साथ लगते जिलों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों में लोगों का जमावड़ा भी होता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा किसान भाइयों को बीमारी की गंभीरता को समझते हुए कोरोना से बचने के प्रयास करने चाहिए। बैठक में गुप्ता ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। यह जंग लंबी हो सकती है। इसलिए 'लड़ाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी' के मंत्र का पालन करें। ■

श्री गुप्ता ने की सभी विधायकों के साथ बैठक

श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि बदलते हालातों में जन-प्रतिनिधियों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। इसलिए विधायकों ने संकट की इस घड़ी में पूरे मनोयोग के साथ जनता का सहयोग करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालातों का जायजा लेने के लिए उन्होंने 22 अप्रैल को प्रदेश के विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों से अपील की कि वे अपने हलके के लोगों को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जारी कोविड प्रोटोकॉल संबंधी हिदायतों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने विधायकों से अपील की कि सामूहिक समारोहों को बढ़ावा न दें और किसी भी स्थान पर लोगों को इकट्ठा न होने दें। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता सुनिश्चित करवाएं। इन स्थानों पर एमएचए की गाइडलाइन का पालन भी सुनिश्चित करवाएं। गुप्ता ने विधायकों से टीकाकरण को प्रोत्साहित करने की भी अपील की।

ऑनलाइन महासम्मेलन में जुटे देशभर के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी

हरियाणा ने अभिनव प्रयोगों से लूटी वाहवाही

देशभर के पीठासीन अधिकारियों के ऑनलाइन सम्मेलन में भाग लेते हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

डिजिटलाइजेशन, महिला सशक्तीकरण और कोविड काल में प्रभावी भूमिका के निभाने के लिए हरियाणा विधान सभा की राष्ट्रीय फलक पर चर्चा हुई है। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की अध्यक्षता में 22 जून को आयोजित देशभर के पीठासीन अधिकारियों के ऑनलाइन सम्मेलन में हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने सिलसिलेवार ढंग से यहां हो रहे अभिनव प्रयोगों का ब्योरा पेश किया। इस पर लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, देश भर की विधान सभाओं के अध्यक्ष और विधान परिषदों के सभापति गदगद दिखाई दिए।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस सम्मेलन का आयोजन गत दो वर्षों में विधान मंडलों की कार्यशैली में आए बदलाव और कोविड काल में उनकी भूमिका की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन में उपस्थित विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों ने अपने यहां हो रहे नवीनतम प्रयोगों की जानकारी दी। इस दौरान उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा विधान सभा में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया पर विशेष चर्चा हुई। हरियाणा विधान सभा के गत बजट सत्र के दौरान 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर महिला सदस्यों को सदन की कार्यवाही सौंपे जाने की दिल खोल कर प्रशंसा हुई।

हरियाणा के अधिकारियों द्वारा विधायकों के फोन न उठाने जाने और इस पर विस अध्यक्ष के संज्ञान के बाद प्रदेश सरकार की ओर से जारी हियायतें भी ऑनलाइन सम्मेलन का हिस्सा बनीं। गुप्ता ने बताया कि 4 नवंबर 2019 को गठित 14वीं विधान सभा में 43 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। इन नवनिर्वाचित विधायकों को प्राथमिकता के आधार सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। प्रश्नकाल के नाम का ड्रा प्रक्रिया से चयन भी उल्लेखनीय उपलब्धी मानी गई। गुप्ता ने बताया कि विधान सभा ने मासिक पत्रिका सदन संदेश का प्रकाशन शुरू कर सदन और सचिवालय की उपलब्धियों की जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस प्रकाशन से जनप्रतिनिधी लेखन और अध्ययन के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधान सभा संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश की सांस्कृतिक धरोधर को लेकर काफी संजीदा है। इस क्रम में विधान सभा के प्रवेश द्वार बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा तथा परिसर के भीतर गीता के प्रतीक स्वरूप कृष्ण-अर्जुन के रथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। ■

वर्चुअल संवाद में सभी दलों के विधायकों ने दिया था सहयोग का आश्वासन

राजनीति से ऊपर उठ लड़ी कोरोना से जंग

हरियाणा विधान सभा सचिवालय में कोविड वेक्सिनेशन ड्राइव का मुआयना करते हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता की ओर से 22 अप्रैल को आयोजित वर्चुअल संवाद में सभी दलों के विधायकों ने राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराया। इस दौरान अनेक विधायकों ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना और घटती ऑक्सीजन की मात्रा पर चिंता जताई तो कुछ ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर अंकुश लगाने की मांग की। वर्चुअल संवाद में अनेक चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए, जिसके मद्देनजर विस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को पत्र लिखकर विधायकों के सुझावों और मांगों से अवगत करवाया। वहीं, श्री गुप्ता ने कहा कि इस वक्त प्रदेश के लोगों को जनप्रतिनियों से सहयोग की दरकार है।

वर्चुअल संवाद के दौरान रोहतक से कांग्रेस विधायक श्री भारत भूषण बत्रा ने अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश में दुकानों का समय शाम 6 बजे तक ही सीमित करना चाहिए। रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि अस्पतालों में बेड की कमी होती जा रही है। इसके लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। गुरुग्राम से विधायक श्री सुधीर सिंगला ने आईएएस अफसरों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक अधिकारी का नाम लेकर कहा कि वे प्रदेश सरकार की योजना से गुरुग्राम में कोरोना के हालात का जायजा लेने आए, लेकिन अपने दौरे की स्थानीय जनप्रतिनिधि को सूचना तक नहीं दी। उन्होंने डॉक्टरों की टीम भेजने के लिए प्रदेश सरकार की तारीफ भी की।

अम्बाला शहर से विधायक श्री असीम गोयल ने कहा कि लोग जनप्रतिनिधियों से काफी अपेक्षा करते हैं। इसके चलते वे अधिकारपूर्वक सहायता भी मांगते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से लेते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीआर में हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इसलिए एनसीआर जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शाम 6 या 7 बजे तक का समय निर्धारण कर सकते हैं।

यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि पेनिक रोकने के लिए सेनेटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोविड अस्पताल में परिजनों को रोगी से मिलने नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से

फैल रही थीं अफवाहें

विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान विधायकों ने कहा कि अनेक असामाजिक तत्व प्रदेश में अजीबोगरीब अफवाहें फैला रहे हैं। बाढड़ा से जजपा विधायक श्रीमती नैना चौटाला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग कोरोना वेक्सीन को लेकर भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। हलके में ऐसी अफवाहें हैं 60 साल से ऊपर के लोगों को सबसे पहले इसलिए वेक्सिन लगाई जा रही है, ताकि उनकी मौत हो जाएं और सरकार को पैंशन न देनी पड़े। इसी प्रकार इसराना से विधायक बलबीर सिंह व फरीदाबाद एनआईटी विधायक श्री नीरज शर्मा ने कहा कि कुछ लोग अस्पतालों में कोरोना से मरने वाले लोगों के अंग निकाले जाने की अफवाहें फैला रहे हैं।

विस कमेटियों की बैठकें स्थगित

देश के अनेक प्रांतों में कोरोना से बिगड़ते हालातों से सबक लेते हुए हरियाणा विधान सभा ने प्रदेश के लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए 22 अप्रैल को बड़े फैसले लिए। आगामी एक माह के लिए विस कमेटियों की सभी बैठकें स्थगित कर गई हैं तो विधानसभा सचिवालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए अफसरों की कमेटी गठित की गई।

संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

नारनौल से विधायक डॉ. अभय सिंह यादव ने कहा कि उनके हलके में हालात काफी संतोषजनक हैं। इसके लिए उन्होंने ईश्वर का आभार व्यक्त किया। असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने मंडियों में किसानों को दिक्कतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बारदाना पर्याप्त नहीं होने के कारण गेहूं की खरीद धीमी गति से हो रही है। इसलिए किसानों को कई दिन तक रुकना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है।

फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस नीरज शर्मा ने विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के इस वर्चुअल संवाद को मिनी विधान सभा बताया। उन्होंने कहा कि इस संवाद में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। इस पर विधान सभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को आश्वासन दिया कि उनकी बात मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा दी जाएगी।

घरोंडा से भाजपा विधायक श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था पूरी हो चुकी है। अब सरकार को चाहिए कि प्राइवेट अस्पतालों की सेवाएं लें। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक राशन वितरण के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग को विशेष सैल बनाना चाहिए। झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि कोरोना महामारी से पूरी मानव जाति पर संकट आया है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोविड से मरने वालों के इलेक्ट्रिक संस्कार की व्यवस्था भी सरकार को विचार करना चहिए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन भी अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जब लोग बचेंगे तभी उनकी मांगों की बात होगी। हिसार से भाजपा विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को वेक्सिनेशन मुहिम को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने अपना उदाहरण बताते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने परिजनों को यह वेक्सीन लगवानी चाहिए तथा इसका प्रचार भी करना चाहिए।

नूह जिले के पुन्हाना हलके से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए। थानेसर से भाजपा विधायक सुभाष सुधा ने शादियों में भीड़ रोकने की बात कही। नारायणगढ़ से विधायक शैली ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना के केसों पर चिंता जताई।

संकट की घड़ी में जनता के साथ रहें

कोरोना काल की संकट की घड़ी में सभी विधायक अपने हलके की जनता के साथ खड़े रहें। निजी स्तर पर होने वाले सामूहिक कार्यक्रम में शिरकत करने से परहेज करें। लोगों से फोन या इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के जरिए संपर्क में रहें। हम सबके सामूहिक प्रयास ही इससे निपटने में कारगर साबित होंगे।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता
अध्यक्ष
हरियाणा विधान सभा

लोगों का मार्गदर्शन भी जरूरी

विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनकी कही बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। इसलिए वे सक्रिय होकर भूमिका निभाएं। संकट काल में ही अपने पराए की परख होती है। इसलिए मेरी माननीय विधायकों के अपील है वे जनता के सहयोगी बनने के साथ उनके साथ मार्गदर्शक भी बनें।

श्री रणबीर गंगवा
उपाध्यक्ष
हरियाणा विधान सभा

विधान सभा सचिवालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष

कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के लिए विधान सभा सचिवालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष भी चालू हो गया है। इस सेवा को त्वरित करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने 22 अप्रैल 2021 को एक विशेष कमेटी का भी गठन किया। विधान सभा के अतिरिक्त सचिव सुभाष शर्मा के नेतृत्व में गठित इस कमेटी में विधान सभा के अधिकारी श्री राजेंद्र पांचाल, श्री यादवेंद्र यादव और श्री संदीप कुमार शामिल रहे। कमेटी 24 घंटे कार्य किया। उधर, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि लोगों की सहायता और अफवाहों को रोकने के लिए जिला स्तर पर समन्वय कमेटियां बनाई जानी चाहिए। इन कमेटियों में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग का इन्फ्रास्टचर काफी बड़ा है, इसके बावजूद इस आपदा की स्थिति में निजी अस्पतालों की सेवाएं भी सरकार को लेनी चाहिए। श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि अफवाहों को रोकना बड़ी चुनौती बन चुका है। अनेक असामाजिक तत्व तथा कुछ लोग निहित स्वार्थों के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाकर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार को ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। गुप्ता ने प्रदेश सरकार को विधायकों के उन सुझावों से भी अवगत करवाया जिनमें स्थानीय स्तर पर सामाजिक संस्थाओं, मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों से मदद लेने की बात कही गई है।

कर्मचारियों को लगा इंजेक्शन, परिजनों की भी सुरक्षा सुनिश्चित

विधान सभा कर्मचारियों ने ली कोविड वेक्सिन की डोज

हरियाणा विधान सभा सचिवालय में कोविड वेक्सिनेशन ड्राइव के मुआयना करते अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने 24 मई को विधान सभा सचिवालय में वेक्सिनेशन ड्राइव का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विधान सभा सचिवालय के 18 से 44 साल के 122 कर्मचारियों को टीका लगाया। मंगलवार को 45 साल से ऊपर के कर्मचारियों और परिजनों को इंजेक्शन लगेगा।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.एस. चौहान के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 मई की सुबह विधान सभा सचिवालय पहुंची। इस टीम में उनके साथ दंत चिकित्सक डॉ. बी.के. दीवान, डॉ. आरती वर्मा, नर्सिंग स्टाफ से आशा और नगमा शामिल रहे। डॉ. बी.के. दीवान ने बताया कि जिन कर्मचारियों को आज इंजेक्शन लगाया गया है, उन्हें 12 से 16 सप्ताह के भीतर दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा।

इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कर्मचारियों को हाल-चाल जाना और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि कोविड वेक्सिनेशन संक्रमण को रोकती है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वेक्सिनेशन के बाद भी सावधानी उतनी ही जरूरी है, जितनी कि इसके लगाने से पहले। उन्होंने कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कर्मचारियों को इम्युनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए खान-पान पर भी विशेष ध्यान रखने को कहा। इसके साथ ही गुप्ता ने विधान सभा सचिवालय पहुंच कर टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार प्रकट किया।

कोविड वेक्सिनेशन ड्राइव के लिए विधान सभा सचिवालय की ओर से विशेष प्रबंध किए गए। इसके लिए कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करवाया। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए शाखा अनुसार सूचियां तैयार की गई। टीकाकरण के लिए कर्मचारियों की बारी आने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित कर बुलाया गया। मंगलवार को इसी व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों को टीका लगाया जाएगा।

विधानसभा कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए यहां 50 फीसदी कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। इन सभी कर्मचारियों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विशेष हिदायतें जारी की गई हैं। इसके अलावा परिसर को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाता है। ■

कोरोना रोगियों से की गई अधिक वसूली वापस दिलाई

जनसेवक की भूमिका में भी नजर आए अध्यक्ष

हरियाणा विधान सभा सचिवालय में पत्रकारों से बात करते विस अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता कोरोना काल में विधानपालिका के मुखिया के साथ-साथ एक जनसेवक की भूमिका में भी नजर आए। इस दौरान वे कोविड रोगियों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लेते रहे, वहीं इस दिशा में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में भी सहभागी हुए। सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाएं कोविड रोगियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए वे प्रशासन और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग की लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे। इस दौरान उनके संज्ञान में निजी अस्पतालों द्वारा रोगियों से अधिक वसूली का मामला आया तो उन्होंने सख्ती भी दिखाई। मामला प्रदेश सरकार तक पहुंचाया और रोगियों ने अनाप-शनाप लिए गए पैसे वापस दिलवाए।

विधान सभा अध्यक्ष के पास हरियाणा के अनेक जिलों के साथ-साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अस्पतालों द्वारा की जा रही अधिक वसूली के खिलाफ शिकायतें कीं। श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार पूरे मनोयोग से लगी हुई हैं। सरकार के बड़े प्रयासों से इस महामारी से निपटने में संतोषजनक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रदेश में अनेक ऐसे तत्व भी सक्रिय हो गए हैं, जो कोविड महामारी को धन कमाने के बड़े व्यावसायिक अवसर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। विधान सभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लिखे पत्र में कहा कि ऐसी गतिविधियों से न केवल मरीजों और उनके परिजनों का घोर आर्थिक शोषण हो रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पंचकूला जिले में कोविड 19 के हालातों पर निगरानी रखने और व्यवस्था संभालने के लिए ज्ञान चंद गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण बड़ी संख्या में लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें निजी अस्पतालों में अधिक वसूली और सरकारी खजाने को चूना लगाने के संबंध में मिलीं।

ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए श्री ज्ञान चंद गुप्ता के निर्देशों पर पंचकूला प्रशासन के एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी निजी अस्पतालों में उपचार के बिलों की जांच करती है। कमेटी ने पाया है कि निजी अस्पतालों में मनमाने ढंग से रुपये वसूले जा रहे हैं। विशेषकर सरकारी कर्मचारियों और बीमित व्यक्तियों के बिलों में बड़ी धांधलियां कर सरकार और बीमा कंपनियों को मोटी चपत लगाई जा रही है। पंचकूला में सबसे ज्यादा शिकायतें शहर में स्थित पारस अस्पताल से जुड़ीं हुई मिलीं। यहां से आने वाली शिकायतों की जांच जिला प्रशासन द्वारा बिलों के संबंध में गठित समिति ने की है। जांच में अनेक चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए। पता चला कि पारस अस्पताल में दाखिल मरीजों का बेरहमी से आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ■

बिल में 4.69 लाख की कटौती

श्री गुप्ता ने बताया कि उनके संज्ञान में जब कोरोना पीड़ित श्री जोग ध्यान का मामला आया तो इसकी जांच कमेटी को सौंपी गई। जोग ध्यान के उपचार के बदले अस्पताल प्रबंधन ने 7 लाख 59 हजार 831 रुपये का प्रोविजनल बिल थमा दिया। इसमें से 2 लाख 95 हजार रुपये का भुगतान भी हो गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक श्री ज्ञान चंद गुप्ता को की। श्री गुप्ता ने कमेटी से मामले की जांच करवाई तो अस्पताल प्रबंधन ने आनन–फानन में बिल में 4 लाख 69 हजार 221 रुपये की कटौती कर दी। अब अस्पताल ने 2 लाख 90 हजार 610 रुपये का बिल बनाया है।

मौत के बाद थमाया 9. 77 लाख का बिल

ऐसा ही एक मामला श्री अशोक कुमार का सामने आया। उसे 24 मार्च 2021 को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अशोक कुमार को बजाज एलायंस की बीमा योजना के तहत कवर किया गया था। इसके बावजूद परिजनों से अस्पताल ने 74 हजार 935 एडवांस जमा करवा लिए। 9 अप्रैल को अशोक कुमार की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। इसके 2 दिन बाद 11 अप्रैल को अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को 9 लाख 77 हजार 17 रुपये का बिल थमा दिया। बिल इतना अनाप–शनाप था कि बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। इस मामले में भी हरियाणा सरकार के दिशानिर्देश की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।

बीमा के बावजूद बना दिया भारी भरकम बिल

तीसरा मामला श्री धर्म पाल सिंघल से जुड़ा है। उन्हें 17 अप्रैल को पारस अस्पताल में भर्ती किया गया था और 3 मई 2021 को छुट्टी दे दी गई थी। रोगी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के तहत बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। इसके बावजूद 4 लाख 97 हजार 724 रुपये का बिल थमा दिया गया। इस बिल में रेडियोलॉजी टेस्ट, लैब टेस्ट, विविध सेवाएं और फिजियोथेरेपी, लैब (आउटसोर्स) और आईपी कंसल्टेशन चार्ज के साथ मेडिकल खर्च (ड्रग्स) दिखाया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने 17 मई 2021 को ईमेल से सूचित किया कि उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कारण यह पाया कि अस्पताल प्रबंधन ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के दिशानिर्देशों को लागू किए बिना भारी भरकम बिल बना दिया। बिलों में रेमेडेविसिर आदि कोविड –19 के उपचार संबंधी हिदायतों की भी घोर उल्लंघना की गई। जांच कमेटी की सिफारिशों के आधार पर श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख कर अनुशंसा की कि प्रदेश के ऐसे सभी अस्पताल के बिलों का ऑडिट करवाकर यह पता लगाना चाहिए कि ये मरीजों को व्यक्तिगत रूप से अधिक वसूली के साथ–साथ सरकार और बीमा कंपनियों को कितनी चपत लगा रहे हैं। उन्होंने ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने को भी कहा है।

मरम्मत कार्य में देरी के लिए विधान सभा अध्यक्ष ने लगाई अफसरों को फटकार, रुके काम करने के निर्देश

दुल्हन की तरह सजेगी हरियाणा विधान सभा

हरियाणा विधान सभा सचिवालय में हरियाणा सरकार और यूटी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने विधान भवन को सजाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस सिलसिले में 7 जुलाई को उन्होंने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन और हरियाणा सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में विधान सभा के सदन से लेकर एमएलए हॉस्टल के पार्कों के रखरखाव पर चर्चा हुई। कार्य में देरी के लिए विधान सभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई।

बैठक में तय हुआ कि तीन माह के भीतर सदन कक्ष को पूरी तरह रेनोवेट किया जाएगा। यूनेस्को की हैरिटेज कमेटी के निर्देशानुसार सदन की दीवारों और पिलरों से लकड़ी की क्लैडिंग हटाई जा चुकी है। सदन की दीवारों के लिए टपैस्ट्री तैयार हो चुकी है। इन टपैस्ट्री से सदन को जहां नया लुक मिल सकेगा, वहीं इस वैश्विक धरोधर का संरक्षण भी हो सकेगा। टपैस्ट्री को दीमक आदि से बचाने के लिए एल्युमिनीयम की सिलिंग से स्थापित किया जा रहा है।

इसके साथ ही विधान सभा सचिवालय के सभी बरामदों और कमरों में नये सिरे से सिलिंग की जा रही है। विधान सभा के भवन के पास स्थित कुलिंग पाउंड के रखाव को लेकर भी विधान सभा अध्यक्ष ने कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि विधान सभा के आसपास के पेड़ों से पत्ते और कई बार जंगली जानवर भी इन टैंकों में गिर जाते हैं। इसके लिए चंडीगढ़ यूटी के अधिकारियों को इसके आसपास फेंसिंग करने की हिदायत दी।

- **चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार के अधिकारियों की बुलाई साझा बैठक**
- **सदन से लेकर एमएलए हॉस्टल तक का होगा कायाकल्प, पार्कों की बदलेगी रंगत**
- **विधान सभा के सदन से लेकर एमएलए हॉस्टल के पार्कों के रखरखाव पर चर्चा**
- **सीआईएसएफ के नाके तक मुख्य सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश**

विधान भवन से लेकर सीआईएसएफ के नाके तक मुख्य सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश भी विस अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने दिए हैं। एमएलए हॉस्टल के सामने स्थित पार्क को विकसित करने की योजना में हो रही देरी पर विधान सभा अध्यक्ष काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पार्क को विकसित करने की योजना करीब 3 वर्ष से लंबित पड़ी है।

इस पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने कहा कि पार्क पर कार्य शुरू कर दिया गया है और एक माह में सिविल वर्क पूरा हो जाएगा। वहीं, यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने पार्क निर्माण के लिए डिजीटल ड्राइंग विधान सभा अध्यक्ष को दिखाई। बैठक में यूटी प्रशासन के मुख्य अभियन्ता सीबी ओझा, एक्सईएन गुरप्रीत सिंह बैंस, सेक्शन इंजीनियर रणजीत सिंह, सीए कपिल सेतिया, हरियाणा सरकार में मुख्य वास्तुकार बीएम शर्मा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त सेक्शन इंजीनियर संजीव चौपड़ा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ■

हवन यज्ञ से की दिन की शुरुआत, कोविड प्रबंध और गौसेवा में बीता दिन

अपने जन्मदिन पर ज्यादा व्यस्त रहे विस अध्यक्ष

पंचकूला के सेक्टर 9 स्थित आयुष डिस्पैंसरी में भगवान धनवंतरी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर पोस्ट कोविड केंद्र का उद्घाटन करते विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता के लिए विशिष्ट दिन 25 मई कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहा। विशिष्ट इसलिए क्योंकि इस दिन उनका जन्मदिन होता है और इस बार यह जन्मदिन पहले की अपेक्षा व्यस्त रहा। उनके नियमित धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ इस बार वे कोविड प्रबंधों में लगे रहे। इस बीच बधाई देने वालों के फोन भी खड़कते रहे।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह सुबह की पूजा-पाठ से हुई। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने घर पर आयोजित हवन-यज्ञ में आहुतियां डालीं। हर बार वे माता मनसा देवी मंदिर में हवन करते थे, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के कारण ऐसा नहीं किया। इसके बाद श्री गुप्ता पंचकूला के सेक्टर 9 पहुंचे और यहां स्थित आयुष डिस्पैंसरी का पोस्ट कोविड केंद्र के रूप में उद्घाटन किया। इसके बाद सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल गए और यहां दाखिल कोविड मरीजों और परिजनों की सेवा की। गुप्ता ने यहां लंगर बांटा और चिकित्सा प्रबंधों का जायजा लिया।

पंचकूला जिले के गांव सुखदर्शनपुर स्थित गौशाला में अपने जन्मदिन पर गायों को हरा चारा खिलाते हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

दोपहर को हलके के गांव सुखदर्शन पहुंचे जहां उन्होंने हाल ही में स्थापित गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया। इसके बाद वे पत्रकारों के बुलावे पर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थापित मीडिया सेंटर गए। यहां उन्होंने कोविड नियमों का पालन करते हुए मीडिया कर्मियों के साथ जन्मदिन मनाया।

श्री गुप्ता ने कहा कि उनके जन्मदिन पर उन्हें हलके की जनता और शुभचिंतकों की तरफ से जिस प्रकार की शुभकामनाएं मिली हैं, उसके लिए वे इन सभी के आभारी हैं। बता दें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुबह ही ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दी थी। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक विधायकों तथा राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भी उनके लिए संदेश प्रेषित किए।

गौरतलब है कि कोविड महामारी के चलते श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने एक दिन पहले ही अपने परिचितों से आग्रह किया था कि उन्हें जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए आवास या कार्यालय पर एकत्रित न हो। उन्होंने सभी से प्रत्यक्ष न मिलने का भी आह्वान किया था। ■

चंडीगढ़ स्थिति हरियाणा विधान सभा सचिवालय में 5 अगस्त को कमेटी सभापतियों की बैठक लेते विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

सरकारी खर्च की पाई-पाई पर रहेगी विधायिका की नजर

हरियाणा विधान सभा ने जनता की खून पसीने की कमाई की पाई-पाई का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। सदन पटल से विकास कार्यों के लिए पास होने वाले बजट का सरकार सही तरीके से प्रयोग कर रही है या नहीं, यह देखने के लिए विधान सभा की कमेटियां अब पहले से ज्यादा सक्रिय होंगी। इस सिलसिले में 5 अगस्त को विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कमेटियों के सभापतियों, अधिकारियों और प्रभारियों के साथ बैठक कर गहन योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक कमेटियां अब नियमित बैठकों के साथ-साथ सीधे जनता के बीच जाकर विकास कार्यों पर संज्ञान लेंगीं।

विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि विधान सभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जवाबदेह है। प्रदेश के मेहनतकश नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स देकर सरकारी खजाना भरते हैं। इस धन को खर्च करने की अनुमति सरकार सदन से लेती है। इसलिए इसका समुचित सदुपयोग सुनिश्चित करवाना विधायिका की जिम्मेदारी है। संसदीय कार्यप्रणाली में सरकारी खर्चों पर निगरानी रखने के लिए कमेटियों का प्रावधान हैं। विकास कार्यों में गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर इन कमेटियों को संज्ञान लेने का पूरा अधिकार है।

गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों में इन कमेटियों ने अनेक विकास कार्यों का मौके पर जाकर मुआयना किया है। इन दौरों से बड़ी मात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग रुका है। गड़बड़ी करने वाले अनेक ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जा सका है तथा संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। याचिका समिति के सभापति घनश्याम दास अरोड़ा ने यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज और हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दौरों का उल्लेख किया। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं विषय पर गठित विषय कमेटी की सभापति सीमा त्रिखा ने बताया कि रक्तदान की धांधली रोकने के लिए उनकी कमेटी ने बड़ा प्रयास किया, इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।

जन स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत और निर्माण पर विषय कमेटी के सभापति दीपक मंगला ने जींद दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा वे पांच विधायकों और अधिकारियों को लेकर शहर पहुंचे तो पाया कि लोक निर्माण विभाग ने सीवरेज की लाइनें बिछाने में पूरी तरह से अंधेरगर्दी की हुई थी। जगह-जगह से टूटे रोड को न तो ठीक किया गया और न ही सीवरेज की लाइनें आपस में जोड़ीं। विभाग की इस कारगुजारी से जनता का धन तो बहुत खर्च हो गया, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल सका। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में मौके पर ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जनता के बीच सकारात्मक संदेश जा सके।

पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति विषय संबंधी कमेटी के सभापति ईश्वर सिंह ने कहा कि जिलों में अधिकारी समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए फंड की कमी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इस पर विस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे मामलों में संज्ञान लेने के लिए कमेटी पूरी तरह से सक्षम हैं। इसके साथ उन्होंने एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर भी निगरानी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कमेटी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक जरूरतमंदों को उनका हक अवश्य मिले। सरकारी आश्वासन समिति के सभापति मोहम्मद इलियास ने भी अपनी बात रखी। इसके साथ की विधान सभा अध्यक्ष ने कमेटियों की अध्ययन यात्राओं को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का आग्रह किया। ■

विधान सभा सचिवालय में 16 अगस्त को गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

मुख्यमंत्री पर हमले के प्रयास पर विस अध्यक्ष सख्त

हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक के मामले में विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी, लेकिन ये रिपोर्ट्स संतोषजनक नहीं होने पर यह मामला विधान सभा की विशेषाधिकारी समिति को सौंप दिया।

रिपोर्ट में आईपीएस अधिकारी श्री पंकज नैन समेत घटना के लिए जिम्मेदार 9 अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ शीघ्र अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई। इनमें से 8 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विधान सभा अध्यक्ष इस कार्रवाई और रिपोर्ट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने डीजीपी से विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी।

पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने पहली रिपोर्ट अपने विशेष मैसेंजर के माध्यम से 15 जून को रिपोर्ट विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता को पहुंचाई। दूसरी रिपोर्ट 16 जुलाई को दी गई। विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता दोनों ही रिपोर्ट्स से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने ने दूसरी रिपोर्ट को पहली से भी कमजोर बताया। विधान सभा परिसर में मुख्यमंत्री के सामने हुई अभद्रता का मामला अब विधान सभा की विशेषाधिकार कमेटी के सम्मुख रख दिया गया है। यह कमेटी पुलिस विभाग के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव द्वारा सौंपी गई दूसरी रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से भी कमजोर है। दूसरी रिपोर्ट में उन अधिकारियों को बचा लिया गया है, जिनके खिलाफ पहली रिपोर्ट में कार्रवाई करने की बात कही गई थी। पहली रिपोर्ट में आईपीएस अधिकारी श्री पंकज नैन समेत घटना के लिए जिम्मेदार 9 अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ शीघ्र अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई थी। इनमें से 8 को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया था। विधान सभा अध्यक्ष पहली रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 7 बिंदुओं पर जवाब तलब किया था। इतना ही नहीं उन्होंने डीजीपी से विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी थी। पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने दूसरी रिपोर्ट में आईपीएस अधिकारी श्री पंकज नैन को क्लीन चिट देते हुए लिखा है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी संतोषजनक ढंग से निभाई है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा नहीं टूटने दिया गया था। रिपोर्ट में विभाग के तीन मुलाजिमों के खिलाफ विभागीय जांच की बात कही गई है। इन कर्मचारियों में एसआई श्री गंगाजल, एएसआई श्री सुबे सिंह, हैड कॉन्टेबल श्री प्रवीण कुमार शामिल हैं।

गौरतलब है कि हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान 10 मार्च को पंजाब के अकाली विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर हमले का प्रयास किया था। इस मामले में विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस महानिदेशक की ओर से भेजी गई पहली रिपोर्ट में बताया गया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए विभाग ने बैठकें की हैं। पुलिस विभाग ने बजट सत्र के लिए जारी विस्तृत सुरक्षा कार्यक्रम के साथ-साथ यहां तैनात कर्मियों का विवरण भी तैयार कर लिया है। ■

महाभारत के युद्ध से हुआ समाज की विचार परंपरा में महान परिवर्तन

हरियाणा ऋषियों और योद्धाओं की भूमि है। धर्म और आध्यात्मिकता की सुगंध इसकी मिट्टी में रची-बसी है। यहां के प्रत्येक गांव का अपना विशिष्ट इतिहास है। देशभक्ति और वीरता इस प्रदेश की पहचान है। सदन संदेश के 'विधान विमर्श' कॉलम इस बार हरियाणा की इन्हीं विशेषताओं को दर्शाने वाली एक कार्यवाही का अंश का प्रस्तुत किया जा रहा है। दरअसल यह अंश पहली विधान सभा में दिए राज्यपाल अभिभाषण से है। यह अभिभाषण प्रथम राज्यपाल श्री धर्म वीरा द्वारा 7 दिसंबर 1966 को दिया गया था।

साथियों! हरियाणा विधान सभा के पहले अधिवेशन पर आप सब का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हरियाणा का नया राज्य, जो भारतीय संघ का 17वां राज्य है, पहली नवंबर, 1966 को अस्तित्व में आया। यह दिन हरियाणा के इतिहास में सदा स्मरणीय दिन रहेगा। (प्रशंसा) मैं इस राज्य की स्थापना पर मैं आप सब को तथा आप द्वारा आपके निर्वाचकों, हरियाणा की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं (प्रशंसा) और इस नए राज्य की प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं।

2. हरियाणा का अतीत बड़ा शानदार रहा है जिस पर किसी भी राज्य को गर्व हो सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इसका भविष्य भी आशाओं से भरपूर तथा उज्जवल है। यह उन ऋषियों की पवित्र भूमि है, जिन्होंने सरस्वती के तट पर वेदों का ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने भगवत् गीता का अमर संदेश कुरुक्षेत्र की यूद्धभूमि में ही दिया था। कुरुक्षेत्र का, जिसे धर्मक्षेत्र कहा गया है, महाभारत युद्ध के साथ अटूट संबंध है। इस युद्ध से समाज की विचार परंपरा में महान परिवर्तन हुआ। इसमें बुराई के विरुद्ध भलाई का निरंतर संघर्ष दिखा कर सच्चाई की विजय होती दिखाई गई है, जो कि भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। तरावड़ी और पानीपत इस राज्य के दो और महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिन्होंने भारत का इतिहास बनते देखा है। इसलिए हरियाणा ऐसा राज्य है जहां धर्म एवं आध्यात्मिकता पनपे हैं तथा इतिहास को स्वरूप मिला है। इसकी परंपरा बड़ी महान है। यहां के लोगों के लिए यह गौरव की बात होगी कि वे परंपराओं को शक्ति और साहस के साथ पुनः प्रचलित करें।

3. हरियाणा के लोगों में देशभक्ति की महान भावना रही है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और बड़ी वीरता से लड़े। हिंदू और मुसलमान बिना किसी भेदभाव के एक होकर लड़े। नारनौल के निकट नसीबपुर, बल्लभगढ़, झज्जर, फरूख नगर, हांसी और रिवाड़ी अद्वितीय वीरता के लिए प्रसिद्ध स्थान हैं। हरियाणा के लोगों को ब्रिटिश सरकार के हाथों जानी नुकसान उठाना पड़ा और उनके इलाके खंडित तथा छिन्न-भिन्न कर दिए गए। परंतु वे इससे घबराए नहीं। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने बाद के वर्षों में भी राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार भाग लिया और अंततः 1947 में ब्रिटिश सरकार से देश स्वतंत्र हुआ। आजादी की लड़ाई में तथा उसके बाद विदेशी आक्रमण के विरुद्ध स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए हरयाणा सबसे आगे रहा है। 1962 में चीणी आक्रमण तथा 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान दोनों बार हरयाणा के वीर सैनिकों तथा अफसरों ने देश की प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए शानदार काम किया। (प्रशंसा) अब भी वे धोखेबाज शत्रु से मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हरयाणा सचमुच ही ऋषियों और योद्धाओं की भूमि है। इसका लगभग हर गांव किसी न किसी रूप में इतिहास में अपना स्थान रखता है। इसलिए मैं हरयाणा के लोगों की देशभक्ति तथा वीरता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। (प्रशंसा) अब चूंकि हरयाणा का नया राज्य एक ऐतिहासिक सच्चाई है, आइए, हम सब इसे अपने सपनों का हरयाणा बनाने के लिए मिलकर प्रयत्न करें और लगातार प्रयत्नों तथा अथक परिश्रम से इस पिछड़े इलाके को प्रगतिशील तथा खुशहाल बना दें। हम हरयाणा के लोगों की देशभक्ति को देश तथा राज्य की सेवा में जुटा दें।

4. प्रशासन के बारे में यह जान कर खुशी होती है कि राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। समाज-विरोधी वर्गों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों तथा भड़काने वाली कार्रवाइयों के होते हुए भी हरयाणा के लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों ने शांति का वातावरण बनाए रखा है। उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि वे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस नवस्थापित राज्य की प्रगति में कोई रुकावट पैदा हो। (प्रशंसा)

5. देश में अनाज की कमी एक ऐसी गंभीर समस्या है, जिसका हरयाणा तथा अन्य राज्यों को सामना करना पड़ रहा है। सप्लाई की कमी है तथा विशाल-क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। हरयाणा राज्य में चावल तो काफी है परंतु गेहूं की कमी है। इस राज्य में अनाज की कमी इस कारण से भी अधिक हो गई है कि उत्तर प्रदेश, जो कि कमी वाला राज्य है, भी उसी खाद्य क्षेत्र के अंदर है, जिसमें हरयाणा और पंजाब है। निस्संदेह कमी वाले क्षेत्रों को अन्य राज्यों से अनाज पहुंचाना होता है। अनाज खुलेआम तथा बिना किसी नियंत्रण के इधर-उधर भेजने से केवल बेईमान व्यापारियों तथा जमाखोरों को ही लाभ होता है, और इससे जन-साधारण की तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसलिए कुछेक ऐसे प्रबंध अपनाए जा रहे हैं जिनमें ये कमियां न हों। चावल तथा बाजरे के समेत सभी प्रकार के अनाज प्राप्त करने के लिए हरयाणा राज्य ने कुछेक जोरदार कदम उठाए हैं। गेहूं के राशन का कुछ भाग इनके द्वारा पूरा किया जाएगा ताकि गेहूं की सप्लाई को बनाए रखा जा सके। अनाज के तस्कर व्यापार तथा जमाखोरी जैसी आम बुराइयों को रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके पास स्वयं खेती करके अथवा किसी ऐसी भूमि से पैदा किया हुआ अनाज पड़ा है जिस के वे किसी भी हैसियत में कब्जाधारी हैं, यह कहा गया है कि यदि उनके पास धान के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई अनाज 10 क्विंटल से अधिक है अथवा सभी प्रकार के अनाज को मिलाकर कुल 25 क्विंटल से अधिक है तो वे उसकी घोषणा करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अनाज के उपलब्ध स्टाक का ठीक प्रकार से वितरण किया जाए।

जाली राशन कार्डों को खत्म करने तथा चोर बाजारी को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। अनाज की दुकानें अब रात को 9 बजे तक खुली रहेंगी ताकि राशन कार्ड वाले किसी भी व्यक्ति को बिना राशन के वापिस न लौटना पड़े। कारखानों के कामगारों तथा कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए कुछेक स्थानों पर अनाज के कुछ और डिपो खोले जा रहे हैं। ऐसा विश्वास है कि ऐसे उपायों से स्थिति में काफी सुधार होगा। परंतु यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकार इन समाज-विरोधी वर्गों तथा उनके नीच कार्यों के विरुद्ध अकेले सफलतापूर्वक नहीं लड़ सकती। ■

संविधान सभा में पेश की भारत के गौरवशाली अतीत की झलक

13 दिसंबर 1946 को भारतीय विधान परिषद की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल में माननीय डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुरु हुई। बैठक की शुरुआत में पं. जवाहर लाल नेहरु ने प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में देश की आजादी, संप्रभुता और गणराज्य की व्याख्या की गई। इसी प्रस्ताव में उन्होंने 'भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र' भी पेश किया। तत्पश्चात श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया। श्री टंडन ने भारत के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए यहां अशोककालीन सभाओं का वर्णन किया। इसके साथ ही उन्होंने पराधीनता काल के संघर्ष और भारत के भविष्य पर भी अपने विचार रखे। सदन संदेश के 'संविधान संकल्पना' कॉलम में हम इसी भाषण के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं

सभापति महोदय, पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का पूरी तौर से मैं समर्थन करता हूं। विधान परिषद् की आज की बैठक एक ऐतिहासिक अवसर है। शताब्दियों के बाद हमारे देश में ऐसी सभा समवेत हुई है। यह सभा हमें अपने वैभवशाली अतीत की याद दिलाती है जब हम स्वतंत्र थे और बड़ी प्रतिनिधि सभायें बैठती थीं जहां बड़े-बड़े विद्वान देश के महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया करते थे। यह हमें अशोककालीन बड़ी-बड़ी सभाओं की याद दिलाती है। उन दिनों का एक धुंधला चित्र आज हमारी आंखों के सामने है। यह सभा हमें अमेरिका, फ्रांस और रूस प्रभृति अन्य देशों की परिषदों की याद दिलाती है। अन्य स्वतंत्र देशों के विधान निर्माण के लिए जो परिषदें बैठी थीं उनके साथ-साथ हमारी यह परिषद् भी सबको सदा याद रहेगी। हम जहां एक ऐसा शासन विधान बनाने बैठे हैं जिससे संसार को यह साफ मालूम हो जाये कि भारत का यह पक्का इरादा है कि वह संसार के साथ मिलकर बाइज्जत रहेगा उससे अलग नहीं। भारत तमाम मुल्कों को सहयोग देगा और उनकी मुसीबतों में उन्हें हरचन्द मदद देगा, वह उन सब प्रयत्नों में साथ देगा जिससे संसार का भला हो। हमें विश्वास है कि हम आज यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह ऐतिहासिक होगा और उसकी गणना भी उन ऐतिहासिक घटनाओं में होगी जिनसे संसार की समुन्नति में सहायता मिली है।

गत डेढ़ सौ वर्षों से हिन्दुस्तान ब्रिटेन के आधीन रहा है। हम उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते जिनके विरुद्ध हमने ब्रिटिश हुकूमत के प्रारम्भ से ही लगातार आवाज उठाई है। इन डेढ़ सौ वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान को जो भी चोटें दी गई हैं, हम यहां उनका जिक्र नहीं करेंगे। उन चोटों ने हमें न केवल अपनी आजादी से ही वंचित किया बल्कि हममें एक आपसी भेदभाव पैदा कर दिया। आज हम उन सब बातों का जिक्र न करेंगे। पर हम अपने नेताओं के त्याग और संघर्ष को नहीं भूल सकते। प्रारम्भ में हमारे नेताओं ने महज प्रस्ताव पास कर और उन्हें सव्याख्या सरकार के पास भेजकर आजादी की मांग की हुकूमत ने खुल्लम-खुल्ला हमारे साथ ज्यादती की और सब जगह अंग्रेजों का पक्ष लिया। हमने शासकों से हर तरह अपील की कि हमारे साथ न्याय का बर्ताव हो। हमारे नेताओं ने उनके ऊंचे आदर्शों की और महामना बर्क और मिल के बताये आदर्शों की

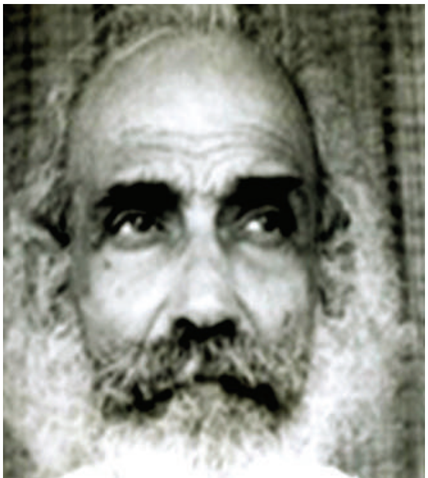

ओर हुकूमत का ध्यान खींचा। हमारे नेता ब्रिटिश आदर्शों से प्रभावित थे और उन्हें पूरी आशा थी कि ब्रिटेन उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें आजादी देगा। वह जमाना अब गुजर गया। अनुभवों ने सिखाया कि आजादी अपील या प्रार्थना से नहीं मिल सकती, उसे पाने के लिए हमें अब बहादुराना कदम उठाना लाजिमी है। हमारे इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उसके बाद नये-नये आंदोलन चलाये गए और ब्रिटेन के साथ खुली बगावत की गई। 1905-06 के आंदोलन ने देश को उन्नति की सीढ़ी पर कुछ और आगे बढ़ा दिया। उस समय हमारे वीर बंगाली नेताओं और युवकों ने ऐसे-ऐसे बहादुराना काम किये जो हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे। हम आगे और राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गांधी राजनीति के मैदान में पहुंचे और उन्होंने हमारे युद्ध का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने हमें एक नया सबक सिखाया और हमने एक नये सिलसिले से लड़ाई शुरू की। ब्रिटिश कानूनों की न सिर्फ अवहेलना ही की गई बल्कि सरेआम वह तोड़े जाने लगे और हमने जरा भी परवाह न की कि इसका क्या कठोर परिणाम भुगतना होगा। हमारे हजारों देशवासियों ने कानून तोड़े और जेल गये। उन वीरों की तस्वीरें जिन्होंने संग्राम में जीवन बलिदान किया या वर्षों जेलों में सड़ते रहे, आज हमारी आंखों के सामने हैं दरअसल अभी हाल का आंदोलन—सन् 1942 का आंदोलन ही इस सभा का जन्मदाता है। ब्रिटेन द्वारा इस परिषद् के बुलाये जाने में इस आंदोलन का जबर्दस्त हाथ है। हमारी आगे की तरक्की के लिए इसने एक नई राह निकाल दी। ब्रिटिश हुकूमत अब भारत में टिक नहीं सकती। इस वास्तविकता को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखें खुल गई और संसार चकित हो गया। दूसरे देशों ने खुलकर तो हमारा साथ नहीं दिया पर हमें यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि हमने अपनी ताकत का इजहार तो किया ही जो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने में खास चीज है। पर साथ ही साथ उन बड़ी ताकतों ने भी जो आज दुनिया को एक करने में लगी हैं हमें सहायता दी है। संसार ने यह समझ लिया है कि दुनिया के एक सुदूर कोने में भी जो अत्याचार किया जाता है, उसका व्यापक असर खुद अत्याचारी के देश पर और उसके पड़ोसी देशों पर पड़ता है। गत दो महायुद्धों ने यह बात प्रमाणित कर दी है। आज संसार के बड़े-बड़े नेता उपाय ढूंढने में लगे हैं कि विश्व को तृतीय महायुद्ध की बर्बादी से कैसे बचाया जाये। वे संसार को स्वर्ग बनाना चाहते है, जहां न और युद्ध होंगे, न इंसान का खून बहाया जायेगा, जहां अमीर और गरीब का भेदभाव न रह जायेगा, जहां हर एक को भोजन और अन्न मिलेगा, जहां हर आदमी को हक हासिल होगा कि वह अपने आदर्शों के अनुसार जीवन यापन करें। जहां प्रत्येक बालक को शिक्षा पाने का अधिकार होगा, जहां आदर्श उच्च और उच्चतर होंगे, जहां निवासियों के बीच एक आत्मिक सम्बन्ध होगा।

बुद्धिमान लोग ऐसे कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे संसार उस दलदल से बाहर निकल सके जिसमें वह आज फंस गया है, जिससे सारे मुल्कों को बराबर हक हासिल हो सके। जमाना तेजी से बदल रहा है और दुनिया की ताकतें इन नये विचारों को अमली रूप देने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही हैं। हम लोग भी जब इसी दुनिया में रहते हैं, उनसे बच नहीं सकते। इन नई शक्तियों का हम भी हृदय से स्वागत करते हैं। ये ही शक्तियां हमारी बड़ी-बड़ी आशाओं का हमेशा आधार रही हैं। भारत के बारे में यह खासतौर से कहा जा सकता है कि उसके निवासियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का ऊंचा आदर्श सदा अपनाया है और संसार को एक देश समझा है। हमारे देश के महापुरुषों ने संसार के मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं माना। बहुत से विदेशी हमारे देश में आये और हमने खुशी से उन्हें अपने गले लगाया।

हमने यह नीति कभी भी अख्तियार नहीं की जिसे कुछ मुल्कों ने आज भारतवासियों के विरुद्ध अपना रखा है हमारा इतिहास बतलाता है कि हमने बाहरी देशों से आये हुए आदमियों का सदा स्वगात किया,

भारत ने अपनाया 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श, संसार को समझा एक देश

आजादी की मांग की हुकूमत ने खुल्लम-खुल्ला ज्यादती की और अंग्रेजों का पक्ष लिया।

अनुभवों ने सिखाया कि आजादी अपील या प्रार्थना से नहीं, हमें अब बहादुराना कदम उठाना लाजिमी है।

महात्मा गांधी राजनीति के मैदान में पहुंचे और उन्होंने हमारे युद्ध का तरीका ही बदल दिया।

ब्रिटिश हुकूमत अब भारत में टिक नहीं सकती। इसको देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखें खुल गईं संसार चकित हो गया।

आज संसार के बड़े-बड़े नेता उपाय ढूंढ़ने में लगे हैं कि विश्व को तृतीय महायुद्ध की बर्बादी से कैसे बचाया जाय।

जो भी सहायता जरूरी थी, हमने उन्हें दी और यहां बसने में उनकी हर तरह मदद की। इंग्लैंड के निवासी ही यहां पहले कैसे आये? उन्हें यहां पनाह दी गई। भारत में झगड़े और लड़ाइयां भी हुई पर इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा मानव अधिकारों की रक्षा की। भाई-भाई के बीच के भेद पैदा करना हम उचित नहीं समझते और न उनके राजनैतिक अधिकारों में ही भेदभाव रखते हैं। इसमें शक नहीं कि हममें कमजोरियां थी और आज भी हैं। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

हमारा अतीत इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। जहां हम समानता के आदर्शों को न सिर्फ अपने देशवासियों के सामने बल्कि दुनिया के सामने रख सकें। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा ख्याल अपने अतीत इतिहास की ओर, गुजरी हुई घटनाओं की ओर जाता है, हमारे संघर्ष और बलिदान की ओर जाता है उस सहायता की ओर जाता है जो हमें दूसरे देशों से मिली है और जिसने आज हमें यहां समवेत किया है। इन सबसे हमें बल प्राप्त करना चाहिए। हम एक ऐसा विधान बनाने के लिए यहां समवेत हुए हैं जिससे देश को सुख शान्ति मिल सके। अपनी मातृभूमि के प्रत्येक निवासी को समानता देना ही हमारा लक्ष्य है।

जो प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया है उसकी तह में समानता का ही सिद्धांत है। देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को स्वायत्त शासन या शासन में खुद मुख्तारी मिली हुई है। और हिन्दुस्तान समूचे को सर्वोपरि राजसत्ता या पूरे अख्तियार रखता है। उन विषयों में जिनमें हम एकता चाहते हैं, हम सब सम्मिलित रहेंगे। प्रस्ताव में सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि इसमें भारत एक आजाद मुल्क माना गया है। हमारा देश सम्मिलित रूप से एक है पर इसके भिन्न-भिन्न अंगों को पूरी आजादी हासिल है कि वे अपने लिए जैसी हुकूमत चाहे रखें। देश का मौजूदा प्रान्तों में विभाजन बदल सकता है। हम सब सम्प्रदायों के साथ न्याय करेंगे और उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पूरी आजादी देंगे।

प्रस्ताव पर इस आशय का एक संशोधन पेश किया गया है कि प्रस्ताव तब तक मुल्तबी रखा जाये, जब तक कि मुस्लिम लीग विधान परिषद् में सम्मिलित नहीं होती। हमें यह लक्ष्य न भूलना चाहिए कि हर एक काम के लिए समय हुआ करता है। अगर आज हम यह प्रस्ताव स्थगित रखते हैं तो फिर कब यह हमारे सामने आयेगा?

हम इस बारे में निश्चित नहीं है कि मुस्लिम लीग कब विधान परिषद् में शामिल होगी। हम आज यहां जब एकत्र हुए हैं तो क्या बिना कुछ किये धरे ही यहां से उठ जायें? क्या हमें कम-से-कम अपनी आगे की कार्यवाही के लिए आज एक लक्ष्य नहीं निश्चित कर देना चाहिए? महज एक निधि निर्माण कमेटी ही बनाकर उठ जायें? हमारे बन्धु हमें यह राय देते हैं कि हम प्रस्ताव पर विचार अभी आगे के लिए स्थगित कर दें। अगर वे यही चाहते थे कि मुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में हम यहां कुछ न करें तो आखिर यहां आये किस लिए हैं?

हम अवश्य चाहते हैं कि मुस्लिम लीग हमें सहयोग दे। पर क्या हम आज उनके वर्तमान अभिलाषाओं और उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ भी हाथ बंटा सकते हैं? हम भरसक कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग के उद्देश्य को किसी तरह नुकसान न पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव में इस बात का ध्यान रखा गया हैं हममें से बहुत ऐसे हैं जो इस बात के खिलाफ हैं कि प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायें।

व्यक्तिगत रूप से मैं खुद मुल्क की भलाई के लिए हिन्दु मुस्लिम तनातनी के कारण प्रान्तों में उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने का विरोध करूंगा। बंगाल तथा और प्रान्त में क्या हुआ? जो हुआ है, उसे हम भली भांति जानते हैं अवशिष्ट अधिकार और राजनैतिक अधिकार (Political Rights) जिनसे देश की उन्नति और एकता में मदद मिल सकती है, केन्द्रीय या संघ सरकार के साथ ही होने चाहिए।

पर यह प्रस्ताव अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को दे देता है, ताकि मुस्लिम लीग यह न कहे कि उनकी गैरहाज़िरी में हमने मनमाने ढंग से काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा प्रकाशित स्टेट पेपर ने भी जो इस परिषद् का आधार है अवशिष्ट अधिकारों (Residuary Powers) को प्रान्तों को देने की बात कही है। हमने इस व्यवस्था को इस आशा से मंजूर कर लिया कि इससे मुस्लिम लीग हमारे साथ मिल-जुल कर काम कर सकेगी।

मुस्लिम लीग हमें सहयोग दे, इस बात के लिए जहां तक साध्य था हम आगे बढ़े। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इसके लिए हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गए। क्योंकि मुस्लिम लीग का लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से बिलकुल प्रतिकूल है। और इससे हमारे भविष्य में काफी कठिनाइयां पैदा होंगी। लीग की सहयोग-प्राप्ति के लिए हमने अपने आदर्शों के प्रतिकूल भी बहुत सी बातें मंजूर कर ली हैं अब हमें यह बन्द कर देना चाहिए और मुस्लिम लीग के साथ समझौते के लिए अपने बुनियादी उसूलों को नहीं भूल जाना चाहिए। ■

सावन की बहार

एमएलए हॉस्टल में तीज के झूलों से झुकीं डाल

हरियाणा विधान सभा में नई परम्पराओं के आगाज़ का सिलसिला जारी है। इस क्रम में यहां 12 अगस्त को महिला स्टाफ की ओर से तीज उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की धर्म पत्नी बिमला गुप्ता मुख्य अतिथि शामिल रहीं।

इस दौरान एमएलए हॉस्टल के सामने स्थित पार्क में बड़े पेड़ पर झूले डाले गए। यहां विधान सभा स्टाफ की महिलाओं ने लोकगीत गाते हुए झूलों का आनंद लिया। इन युवतियों में नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी भी शामिल रहीं। तीज उत्सव के दौरान पार्क में सजे झूले जहां बागों की बहार का अनुभव करवा रहे थे, वहीं इस अवसर आयोजित इंडोर कार्यक्रमों में महिला स्टाफ ने जमकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस दौरान हर किसी के पैर हरियाणवी नृत्य पर थिरकते नजर आए तो तंबोला की मस्ती भी सिर चढ़कर बोलती रही। म्यूजिक चेयर गेम में ठहाकों का दौर लगातार जारी रहा।

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की धर्म पत्नी बिमला गुप्ता ने कहा कि महिला स्टाफ ने इस प्रकार का आयोजन करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। भारतीय संस्कृति उत्सवधर्मी संस्कृति है। यहां का हर दिन उत्सव है, लेकिन सावन में आने वाला तीज पर्व हमें मस्ती के साथ-साथ अपने धर्म और संस्कृति जुड़ने की प्रेरणा भी देता है। विधान सभा की अवर सचिव प्रदीप कौर कहती हैं कि इस प्रकार का उत्सव विधान सभा में पहली बार मनाया गया है, जिसमें हर उम्र की महिलाओं ने जमकर आनंद लिया। अवर सचिव सरोज कुमारी ने कहा कि

हरियाणा विधान सभा की ओर से पहली बार मनाया गया तीज उत्सव

विधान सभा अध्यक्ष की प्रेरणा और प्रयासों इस प्रकार कार्य संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष के परिवार ने जिस आत्मीयता के साथ इस कार्यक्रम में भागीदारी की, उससे कार्यक्रम की छटा ही बदल गई। पूरे कार्यक्रम में पारिवारिक माहौल बना रहा। बिल शाखा में अधीक्षक रुपिंदर कौर ने कहा कि विधान सभा की महिला कर्मचारियों के लिए इस बार तीज का त्योहार एक सौगात के रूप में आया है। अध्यक्ष जी ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं करवाकर महिलाओं का उत्साह दोगुना कर दिया। विधान सभा में पुस्तकालय प्रभारी ज्योति कादियान ने कहा कि तीज हमारी संस्कृति का प्रतीक है। विधान सभा में इस प्रकार के आयोजन से महिला स्टाफ में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव और बढ़ा है। विधान सभा में टेलिफोन ऑपरेटर कृष्णा शर्मा कहा कि इस प्रकार के आयोजन से मातृ शक्ति का सम्मान बढ़ा है। निजी सहायक सरला रानी ने अपनी भावनाएं इस कविता के माध्यम से व्यक्त कीं...

विधान सभा के महिला स्टाफ द्वारा मनाए जाए रहे तीज उत्सव की झलकियां...

सावन की फुहार

आया तीज का त्योहार
सखियों हो जाओ तैयार
करके सोलह श्रृंगार।
आया तीज का त्योहार,
मन हर्षित हुआ अपार।
तीज का त्योहार,
करदे आपकी जिंदगी में
खुशियों की बौछार।

- सरला रानी
निजी सहायक

तीज की मल्हार

हल्की-हल्की फुहार थीं,
ये सावन की बहार थीं
मिल जुलकर सब झूले थे
क्योंकि ये तीज की मल्हार थी।
झूम उठे थे दिल सभी के,
इसके गीतों के तराने से
जुड़ गए थे टूटे सम्पर्क
बस झूलने के बहाने से।
इस तीज की पावनता पर
मिलकर झूला था सबने
एक दूजे के सहयोग से
आसमान को छुआ था सबने।
एकजुट होकर आए सारे
एक ही सुर में गाए सारे
यही कहते हैं संस्कार हमारे
मिल जुलकर तीज मनाएं सारे।

- एकता
स्टैनो, मीडिया एवं
अनुसंधान शाखा

तीज की धूम

झूमी धरती, उपवन हरे

ऐतिहासिक तीज महोत्सव
हरियाली तीज का सुअवसर है
छाया सुरूर हम सभी पर है
एम.एल.ए. हॉस्टल के प्रांगण में
झूले डले हैं पेड़ों पर
झूल रही हैं सखियां सब
गूंज रही किलकारी है
झूम रही ये धरती भी अब
है हरा भरा ये वन उपवन
चहक रही हैं कोयल कूं कूं
फैल गई है उमंग हरसू
श्री ज्ञान चंद जी के अथक प्रयासों से
पाया हमने यह अवसर है
जो हो न सका कई बरसों में
कर दिया उसे संभव कल परसों में
रच दिया इतिहास पुनः उन्होंने
दिया नारी को सम्मान।
कहा- खूब मनाओ तीज और
सावन रखूंगा तुम्हारा मान।।

- वंदना शर्मा
सहायक
सीए/टीए शाखा

हरियाणा के उत्थान की झलक है सदन संदेश

♦ प्रो. सतबीर कश्मीरी

कॉलेज में मई, 2021 की 'सदन संदेश' पत्रिका दिखी। हाथ स्वतः ही उस ओर बढ़ गए। उसके बाहरी आवरण ने मन मोह लिया। डॉ. भीमराव जी की प्रतिमा व उनके शब्द 'हम भारतीय हैं सबसे पहले भी और अंत में भी।' मन में रम गए। विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से विधान सभा के प्रवेश द्वार पर भीमराव जी की ताम्र धातु से निर्मित सात फुट ऊंची प्रतिमा लगवा, हरियाणा राज्य में समानता, न्याय, बंधुता की मंगल तान को और और मधुर बनाने का सराहनीय कार्य किया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा भी प्रत्येक प्रांत वासी में साहस व प्रेम का संचार कराती है। इन कार्यों हेतु श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को सादर नमन।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी के कथनों में जो उन्होंने माननीय विधायकों के लिए कहे 'वे अपने हलके में जनता के साथ खड़े हों। वे निजी स्तर पर होने वाले सामूहिक कार्यक्रम में शिरकत करने का परहेज करें। लोगों से फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपर्क में रहें। विधायक जनता का प्रतिनिधि हैं। लोग उनकी कही बातों को गंभीरता से लेते हैं इसलिए वे सक्रिय होकर भूमिका निभाएं' शब्दों से मानो पटेल, अटल, उपाध्याय जी बोलते नजर आए। किसानों को स्नेह भरा आशीष देते नजर आए। इस महामारी काल में वीर योद्धाओं (स्वास्थ्य कर्मी व डॉक्टरों को) वे भूला नहीं पाए। यही आदर्श व्यक्तित्व की पहचान होती है जिनमें जन साधारण के प्रति चिर स्थाई सेवा भाव बसा रहता है।

श्री दिनेश कुमार (मीडिया व संचार अधिकारी हरियाणा विधानसभा) के शब्द 'किसी भी विधानसभा का सदन जनाकांक्षा की अभिव्यक्ति और संवाद का सबसे उपयुक्त मंच होता है।' ने मन मोह लिया। महोदय ने भारतीय प्राचीन शासन प्रणाली के विभिन्न रूपों के दर्शन करा, वर्तमान संविधान के प्रति और स्नेह व विश्वास बढ़ाया।

सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रणाली ने भी मन मोह लिया जहां पक्ष-विपक्ष से बढ़कर आदर्श व्यक्तित्व, संस्कारों को तवज्जो देने की बात निष्पक्षता से स्वीकारी गई।

विधान विमर्श में संसदीय इतिहास की झांकी में 'ताकतवर सत्ता पक्ष कमजोर विपक्ष को दबा नहीं सकता' चौधरी रामस्वरूप सांपला के व 'लोगों की समस्याएं सुनने से सशक्त होती है सरकार' कामरेड राम व्यास, करनाल के कथनों ने हृदय पर अमिट छाप छोड़ी।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि भाषणों के साथ यदि दिनांक भी (कि किस तिथि को भाषण दिया गया था) हो तो तत्कालीन परिस्थितियों को मस्तिष्क में ला धूमिल छवि को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। इसे सुझाव के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। कामरेड राम प्यारा के शब्द 'अगर

गवर्नमेंट लोगों के ग्रीवेंसिज सुनने को एक दिन दे देती है तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के हाथ मजबूत होते हैं।' अच्छे लगे। उनमें आदर्श हरियाणा निर्माण के स्वप्न थे जिन्हें पूरा करने को वे छटपटा रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के बचपन का सरपंच बरकत राम विज वाला प्रसंग, हरियाणा ही नहीं पूरे राष्ट्र के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का, जगाने का और मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता नजर आता है।

साक्षात्कार में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने के आदर्श-संस्कारी व राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व के दर्शन हर प्रांत वासी को इस निश्चिंतता से भर देते हैं कि प्रांत हरियाणा सुरक्षित व मजबूत हाथों में है और निरंतर विकास पथ की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री महोदय जी का साक्षात्कार पढ़ उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ पंक्तियां मैंने लिखीः-

'महम निंदाना में थे जन्मे, धनपत सांगी गाम था
महापुरुषों के चित्र बनाना, उस बालक का काम था
दसवीं कक्षा प्रथम वे आए, डॉक्टर बनना चाहते थे
जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक से, वे राष्ट्र बदलना चाहते थे

अमिट स्नेह रखते अंबेडकर, हृदय से पूजन करते हैं
प्रयास से इनके विधानसभा, भीमराव जी सजते हैं
पीड़ा समझी भीम कि उनका, ध्येय निज ध्येय बनाया
खड़े हाशिए लोगों खातिर, सेवक बन के आया।
प्रयोग निरंतर करने को, मार्ग बताया विकास का
आदर्श राज बनाने खातिर, मार्ग यही विश्वास का।'

प्रश्नकाल को पढ़ते हुए कथन 'विधायकों के सवालों में झलकती है जनता की जरूरतें और भावनाएं भी' मन को हर गया। माननीय विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को जन-जन तक पहुंचाना भी साहस का कार्य होता है। जो 'सदन संदेश' पत्रिका ने बखूबी निष्पक्षता के साथ निभाया।

पृष्ठ संख्या 24 और 25 भी विशेष रहा। भीमराव अंबेडकर जी का संक्षिप्त परंतु हृदय उद्वेलित कर देने वाला परिचय पढ़ने को मिला। उनके मूकनायक व बहिष्कृत भारत के प्राचीन समाचार पत्रों ने भीमराव, संविधान व निष्पक्ष हरियाणा सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा दिया।

भविष्य में डिजिटलाइजेशन से विधानसभा और परिष्कृत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। कागजों की बचत होगी। प्रतिनिधिमंडल का शिमला जाकर डिजिटल विधानसभा की बारीकियों को समझना बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा अन्य राष्ट्रों के संविधान पढ़, उनके आदर्शों का चयन करने की स्मृति लाता है जो इस दिशा में आदर व सार्थक प्रयास है।

पत्रिका में नारी सम्मान व उनके विकास व निरंतर आगे बढ़ते हुए उन्हें साथ लेकर चलने का जिक्र किया गया जिससे पता चलता है कि प्रांत में नारियों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। उनके अधिकारों को सुना जाता है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। समाहार रूप में कहा जा सकता है कि 'सदन संदेश पत्रिका में निरंतर विकास की ओर बढ़ता गौरवान्वित होता हरियाणा अपने विकास गाथा गाता नजर आता है। पत्रिका में हरियाणा का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान-विकास झलकता नजर आता है साथ ही वर्तमान हरियाणा सरकार की निष्पक्षता-पारदर्शिता व जन हितैषी, समाज के प्रत्येक वर्ग खातिर निरंतर प्रयासरत आदर्श सरकार के दर्शन होते हैं।' आगामी पत्रिका का बड़ी बेसब्री से इंतजार है।

(लेखक सोनीपत जिले में मुरथल स्थित ताऊ देवीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय में सहायक आचार्य हैं।)

अक्तूबर माह में हरियाणा विधानसभा के नौ विधायकों के जन्मदिन हैं। माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने इन सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य एवं सुयशस्वी जीवन की कामना की है।

श्री विनोद भयाणा, हांसी
जन्मः 02 अक्तूबर 1957
रुचिः भारतीय इतिहास पढ़ना

श्रीमती शैली चौधरी, नारायणगढ़
जन्मः 02 अक्तूबर 1966
रुचिः धार्मिक कार्य

श्री प्रमोद कुमार विज, पानीपत शहर
जन्मः 04 अक्तूबर 1955
रुचिः संगीत तथा यात्रा करना

श्री सुरेंद्र पंवार, सोनीपत
जन्मः 08 अक्तूबर 1968

श्री सुधीर सिंगला, गुरुग्राम
जन्मः 13 अक्तूबर 1965
रुचिः क्रिकेट, पढ़ना

श्री मोहन लाल बडौली, राई
जन्मः 15 अक्तूबर 1961
रुचिः इतिहास पढ़ना तथा उसकी तुलना वर्तमान से करना

श्रीमती नैना सिंह चौटाला, बाढड़ा
जन्मः 15 अक्तूबर 1966
रुचिः इंटीरियर डिजाइनिंग, बागवानी, कुकिंग

श्रीमती कमलेश ढांडा, कलायत
जन्मः 18 अक्तूबर 1967
रुचिः योगा

श्री असीम गोयल नन्यौला, अंबाला शहर
जन्मः 25 अक्तूबर 1979
रुचिः पुस्तकें पढ़ना, फिल्में देखना, यात्रा, सैर करना

लोकतंत्र को सही अर्थों में कायम रखने
और इसे उत्तरोत्तर विकसित करने के लिए
हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों
की ओर तेजी से आगे बढ़ना होगा। लोगों
के सामाजिक और आर्थिक जीवन में
क्रांतिकारी बदलाव शांतिपूर्ण तरीके से
संभव है।

-ज्ञान चंद गुप्ता
माननीय अध्यक्ष
हरियाणा विधान सभा